अध्याय I

केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों के वित्तीय निष्पादन का सारांश

1.1 प्रस्तावना

यह प्रतिवेदन सरकारी कम्पनियों, सांविधिक निगमों और सरकार नियंत्रित अन्य कम्पनियों के वित्तीय निष्पादन का सारांश प्रस्तुत करता है। इस प्रतिवेदन में शब्द केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम (सीपीएसई) में उन सरकारी कम्पनियों को शामिल किया गया है जिनमे केंद्र सरकार की प्रत्यक्ष धारिता 50 प्रतिशत या अधिक है तथा ऐसी सरकारी कम्पनियों की सहायक कम्पनियां शामिल है। संसद द्वारा अधिनियमित संविधियों के अंतर्गत स्थापित संविधिक निगमों और केन्द्र सरकार द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से स्वामित्व वाली या नियंत्रित अन्य कंपनियों को भी सीपीएसई के रूप में श्रेणीबद्ध किया गया है।

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(45) में एक सरकारी कम्पनी की परिभाषा ऐसी कम्पनी के रूप में दी गयी है जिसमें प्रदत्त शेयर पूंजी का कम से कम 51 प्रतिशत केन्द्र सरकार, अथवा किसी राज्य सरकार या सरकारों या आंशिक रूप से केन्द्र सरकार द्वारा तथा आंशिक रूप से एक या अधिक राज्य सरकारों द्वारा धारित है और इसमें वह कम्पनी भी शामिल है जो सरकारी कम्पनी की सहायक कम्पनी है।

सरकारी कंपनी

एक कम्पनी जिसमें प्रदत्त शेयर पूंजी का कम से कम 51 प्रतिशत केन्द्र सरकार, अथवा किसी एक या अधिक राज्य सरकारों या आंशिक रूप से केन्द्र सरकार द्वारा तथा आंशिक रूप से केन्द्र सरकार और राज्य सरकार (रों) द्वारा धारित है तथा इसमें सरकारी कम्पनी की सहायक कम्पनी सम्मिलित होती है।

इसके अतिरिक्त, केंद्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार या सरकारी या केंद्रीय सरकार द्वारा आंशिक रूप से और एक या अधिक राज्य सरकारों द्वारा आंशिक रूप से प्रत्यक्ष या

अप्रत्यक्ष रूप से स्वामित्व या नियंत्रण वाली किसी अन्य कंपनी[1] को इस प्रतिवेदन में सरकार नियंत्रित अन्य कम्पनियों के रूप में दर्शाया गया है।

सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) ने पीई द्वारा प्रकाशित सर्वेक्षण 2019-20 में बताया (अगस्त 2021) कि सांविधिक निगमों के अलावा सीपीएसई वह सरकारी कम्पनियां है; जिनमें 50 प्रतिशत से अधिक शेयर केन्द्र सरकार द्वारा धारित था। इन कम्पनियों की सहायक कम्पनियों, यदि भारत में पंजीकृत है, को भी सीपीएसई के तौर पर श्रेणीबद्ध किया जाता है। इसमें विभागीय तौर पर चालित सार्वजनिक उद्यम, बैंकिंग संस्थान एवं बीमा कम्पनियाँ शामिल नहीं है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएजी) एवं डीपीई द्वारा अपनाई गई परिभाषा में अंतर को देखते हुए, सीएजी एवं डीपीई द्वारा सीपीएसई मानी गई कम्पनियों की संख्या में अंतर हो सकता है।

1.1.1 अधिदेश

सरकारी कम्पनियों और सरकार नियंत्रित अन्य कम्पनियों की लेखापरीक्षा सीएजी के (कर्त्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19 के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) से 143(7) के प्रावधानों तथा उनके अंतर्गत बनाए गए विनियमों के अन्तर्गत सीएजी द्वारा की जाती है। कम्पनी अधिनियम, 2013 के अन्तर्गत, सीएजी सरकारी कम्पनियों और सरकार नियंत्रित अन्य कम्पनियों के लिए सांविधिक लेखापरीक्षकों के रूप में सनदी लेखाकारों की नियुक्ति करता है और उस तरीके पर निर्देश देता है जिससे लेखाओं की लेखापरीक्षा की जानी है। इसके अतिरिक्त, सीएजी को अनुपूरक लेखापरीक्षा करने का अधिकार है। कुछ सांविधिक निगमों को शासित करने वाली संविधियों में उनके लेखाओं का सीएजी द्वारा लेखापरीक्षा की अपेक्षा की गई है।

भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय निर्यात-आयात बैंक, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक तथा राष्ट्रीय आवास बैंक को शासित करने वाले अधिनियमों में वे प्रावधान निहित हैं जिनके द्वारा केन्द्र सरकार इन संस्थानों के लेखाओं की जांच करने और उन पर रिपोर्ट

[1] *गजट अधिसूचना दिनांक 4 सितम्बर 2014 के माध्यम से कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी किए गए कंपनियों का (कठिनाइयों का निवारण) सातवां आदेश 2014*

करने के लिए भी सीएजी को लेखापरीक्षक के रूप में नियुक्त कर सकती है। 2019-20 के दौरान ऐसी कोई नियुक्ति नहीं की गई थी।

1.1.2 इस प्रतिवेदन में क्या है

इस प्रतिवेदन में केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के वित्तीय निष्पादन की समग्र स्थिति को दर्शाया गया है जैसा कि उनके खातों से पता चला है।

लेखाओं के संशोधन तथा वर्ष 2019-20 (अथवा पिछले वर्षों के, जिन्हें चालू वर्ष के दौरान अन्तिम रूप दिया गया है) के लिए सीएजी द्वारा की गई सीपीएसई के वित्तीय विवरणों की अनुपूरक लेखापरीक्षा के परिणामस्वरूप की गई महत्वपूर्ण टिप्पणियों, का प्रभाव प्रतिवेदन में दिया गया है। इस प्रतिवेदन में सांविधिक निगमों के वित्तीय विवरणों पर सीएजी द्वारा जारी टिप्पणियों का प्रभाव भी निहित हैं जहां सीएजी ही एकमात्र लेखापरीक्षक है।

यह प्रतिवेदन कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के सीपीएसई द्वारा पालन तथा कार्पोरेट सामाजिक दायित्व पर डीपीई द्वारा जारी दिशानिर्देशों, सीपीएसई में विनिवेश तथा गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों द्वारा भारतीय लेखांकन मानको (इंड एएस) के कार्यान्वयन की स्थिति का पूर्ण चित्रण भी प्रस्तुत करता है।

1.1.3 सीपीएसई की संख्या

31 मार्च 2020 को सीएजी के लेखापरीक्षा क्षेत्राधिकार के अंतर्गत 697 सीपीएसई थी। इनमें 488 सरकारी कंपनियाँ[2], छह सांविधिक निगम[3] तथा

सरकारी कंपनियाँ	488
सांविधिक निगम	6
सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनियाँ	203
कुल सीपीएसई	697

[2] *488 सरकारी कंपनियों में 231 स्टेडअलोन/होल्डिंग सरकारी कंपनियाँ तथा 257 सहायक व होल्डिंग सरकारी कंपनियों के संयुक्त उद्यम (जेवी) शामिल हैं।*

[3] *भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई), केन्द्रीय भण्डारण निगम (सीडब्ल्यूसी), दामोदर घाटी निगम (डीवीसी), भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई), भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (आईडब्ल्यूएआई) तथा भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई)।*

203 सरकार नियंत्रित अन्य कंपनियाँ शामिल थी। इनमें से 607 सीपीएसई के वित्तीय निष्पादन का सारांश इस प्रतिवेदन में शामिल किया गया है और इन सीपीएसई की प्रवृत्ति तालिका 1.1 में दर्शाई गई है:

तालिका 1.1: इस रिपोर्ट में शामिल सीपीएसई की कवरेज और प्रकृति

सीपीएसई की प्रकृति	कुल सीपीएसई की संख्या	प्रतिवेदन में शामिल सीपीएसई की संख्या				इस प्रतिवेदन में कवर नहीं किए गए सीपीएसई की संख्या
		निम्न तक लेखे			कुल	
		2019-20	2018-19	2017-18		
सरकारी कम्पनियां	488	400	17	4	421*	67
सांविधिक निगम	6	5	1	0	6	0
कुल कम्पनियां/ निगम (क)	494	405	18	4	427	67
सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कम्पनियां (ख)	203	174	5	1	180	23
जोड़ (क+ख)	**697**	**579**	**23**	**5**	**607**	**90**

***421 सरकारी कम्पनियों में से, केन्द्र सरकार के पास 193 सीपीएसई में प्रत्यक्ष होल्डिंग है। शेष 228 सीपीएसई इन 193 सीपीएसई की सहायक तथा संयुक्त उद्यम (जेवी) हैं।**

2019-20 के दौरान सीएजी के लेखापरीक्षा क्षेत्र के अंतर्गत आयी/ बाहर चली गई, सरकारी कम्पनियों/सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कम्पनियों के विवरण *परिशिष्ट-I* में दिए गए हैं।

इस प्रतिवेदन में 90 सीपीएसई (23 सरकार नियंत्रित अन्य कंपनियों सहित) शामिल नहीं है, जिनके लेखे तीन वर्ष या अधिक से बकाया थे या समाप्त/परिसमापनाधीन थे या प्रथम लेखे बकाया नहीं थे। इन सीपीएसई को दो सितारों (**) के द्वारा *परिशिष्ट-//क* तथा *परिशिष्ट-//ख* में दर्शाया गया है।

इस प्रतिवेदन में शामिल सरकारी कंपनियाँ और सांविधिक निगम के वित्तीय निष्पादन का सारांश	
सीपीएसई की संख्या	494
कवर किये गये सीपीएसई	427
प्रदत पूंजी (427 सीपीएसई)	₹ 6,33,159 करोड़
दीर्घावधि पूंजी (427 सीपीएसई)	₹ 22,66,674 करोड़
बाज़ार पूंजीकरण (58 सूचीबद्ध ट्रेडेड सरकारी कंपनियाँ)	₹ 8,39,970 करोड़
निवल लाभ (224 सीपीएसई)	₹ 1,40,976 करोड़
निवल घाटा (181 सीपीएसई)	₹ 68,434 करोड़
शून्य लाभ/हानि (22 सीपीएसई)[4]	
घोषित किया गया लाभांश (99 सीपीएसई)	₹ 73,487 करोड़
कुल परिसंपत्ति (427 सीपीएसई)	₹ 56,83,065 करोड़
उत्पादन का मूल्य (427 सीपीएसई)	₹ 22,14,077 करोड़
निवल मूल्य (427 सीपीएसई)	₹ 16,36,946 करोड़

1.2 सरकारी कंपनियों और निगमों में निवेश

31 मार्च 2020 के अंत तक 427 सरकारी कंपनियों और निगमों[5] में इक्विटी और ऋणों में निवेश की राशि, तालिका 1.2 में दिए गए है:

[4] *427 में से, 22 सीपीएसई ऐसे थे जिन्होंने 2019-20 के दौरान कोई लाभ नहीं कमाया या कोई नुकसान नहीं था क्योंकि या तो ऑपरेशन शुरू नहीं हुए थे या नुकसान/ निवल व्यय को परियोजना लागत के साथ समायोजित किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की हानि को निवल स्थापना व्यय के रूप में उसकी अचल संपत्तियों में स्थानांतरित किया गया था तथा भारतीय अंतदेशीय जलमार्ग प्राधिकरण की हानि को इसके आईडब्ल्यूएआई निधि के साथ समायोजित किया गया था। इसीलिए इन दो सांविधिक निगमों को भी शून्य लाभ/हानि सीपीएसई के रूप में माना गया है।*

[5] *494 सीपीएसई-67 सीपीएसई जिनके लेखे तीन साल या उससे अधिक के लिए बकाया थे या विचलन/अधीन परिसमापन थे या पहले लेखे देय नहीं थे।*

तालिका 1.2: सरकारी कंपनियों और निगमों में इक्विटी और ऋण

(₹ करोड़ में)

निवेश के स्रोत	31.03.2020 को			31.03.2019 को		
	इक्विटी	लंबी अवधि के ऋण	जोड़	इक्विटी	लंबी अवधि के ऋण	जोड़[6]
1. केन्द्र सरकार	4,52,908	3,04,899	7,57,807	4,04,423	2,83,216	6,87,639
2. केन्द्र सरकारी कंपनियाँ/ निगम	84,055	51,866	1,35,921	65,911	46,000	1,11,911
3.राज्य सरकारें/राज्य सरकारी कंपनियाँ/ निगम	32,596	23,039	55,635	29,761	19,647	49,408
4. वित्तीय संस्थाएं और अन्य	63,600	18,86,870	19,50,470	48,323	14,57,427	15,05,750
कुल	**6,33,159**	**22,66,674**	**28,99,833**	**5,48,418**	**18,06,290**	**23,54,708**
कुल निवेश के प्रति केंद्र सरकार के निवेश का प्रतिशत	71.53	13.45	26.13	73.74	15.68	29.20

स्रोत: वर्ष 2018-19 और 2019-20 के लिए सीपीएसई के लेखापरीक्षित लेखे

यह पाया गया था कि सरकारी कम्पनियों तथा निगमों में कुल निवेश 2018-19 के मुकाबले 2019-20 के दौरान ₹ 5,45,125 करोड़ (23.15 प्रतिशत) बढ़ गया था जिसमें इक्विटी में ₹ 84,741 करोड़ की वृद्धि तथा दीर्घकालिक ऋणों में ₹ 4,60,384 करोड़ की वृद्धि शामिल थी।

1.2.1 इक्विटी होल्डिंग

2019-20 के दौरान, इस रिपोर्ट में शामिल 427 सीपीएसई में इक्विटी के अंकित मूल्य पर कुल निवेश ₹ 84,741 करोड़ की निवल वृद्धि दर्ज की गई। 2019-20 के दौरान सीपीएसई

[6] *कुछ सीपीएसई के संबंध में, पिछले वर्ष के अनंतिम आंकड़ों को प्राप्त खातों के साथ अद्यतन किया गया है।*

में अंकित मूल्य पर केंद्र सरकार की इक्विटी होल्डिंग ₹ 48,485 करोड़[7] तक बढ़ी। ₹ 48,485 करोड़ की वृद्धि, 37 सीपीएसई में ₹ 53,739 करोड़ के अंकित मूल्य वाले शेयरों के जारी करने और 24 सीपीएसई[8] में ₹ 5,254 करोड़ के अंकित मूल्य वाले शेयरों के विनिवेश और पुन: खरीद का परिणाम थी।

वर्ष 2019-20 के दौरान केंद्र सरकार द्वारा ₹ 53,739 करोड़ के नए इक्विटी निवेश में से, ₹ 52,192 करोड़ की इक्विटी निवेश 33 सीपीएसई में इक्विटी के रूप में संबंधित था जो सीपीएसई में नकदी प्रवाह था और ₹ 1,547 करोड़ का निवेश दो सीपीएसई[9] में बोनस शेयरों के जारी करने के रूप में था। दो सीपीएसई[10] में भी परिसंपत्तियों का इक्विटी में हस्तांतरण में संबंधित सीपीएसई को नकद प्रवाह शामिल नहीं था। सीपीएसई में नकदी प्रवाह के रूप में सम्मिलित ₹ 52,192 करोड़ के इक्विटी के नए निवेश के उद्देश्य की लेखा परीक्षा में समीक्षा में संकेत दिया गया कि ₹ 45,810 करोड़ का नकद इन्फयूजन 25 सीपीएसई में पूंजीगत व्यय को पूरा करने के लिए था, ₹ 5,600 करोड़ दो सीपीएसई[11] में पूंजीगत तथा राजस्व दोनों मदों को पूरा करने के लिए थे तथा ₹ 782 करोड़ छह सीपीएसई[12] में राजस्व मदों को पूरा करने के लिए थे।

सरकारी कंपनियों और निगमों में 31 मार्च 2020 को समाप्त तीन वर्षों के दौरान केंद्र सरकार और अन्य[13] द्वारा इक्विटी में धारिता को चार्ट-1.1 में दर्शाया गया है।

---

[7] *इस लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में 18 सीपीएसई के अनंतिम आंकड़ों को उनके अंतिम लेखापरीक्षा किए गए लेखाओं के आंकड़ों के आधार पर शामिल किया गया है क्योंकि रिपोर्ट तैयार करने के लिए कट-ऑफ की तारीख (31 दिसबंर 2020) से पहले वर्ष 2019-20 के लेखा प्राप्त नहीं हुए थे।*

[8] *औद्योगिक तथ वित्तीय पुर्ननिर्माण बोर्ड (बीआईएफआर) के फैसलों के कारण एनईपीए की पूंजी कम हो गई।*

[9] *आरआईटीईएस लिमिटेड, गेल (इंडिया) लिमिटेड*

[10] *हेमीसफीयर प्रोपट्रीज इंडिया लिमिटेड, डीएनएच पावर डिस्ट्रीब्यूसन कॉरपोरेशन लिमिटेड*

[11] *नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड, ईसीजीसी लिमिटेड*

[12] *इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक लिमिटेड, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड, राष्ट्रीय विकलांग वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम लिमिटेड, राष्ट्रीय सफाई कर्माचारी वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड।*

[13] *अन्य में केंद्र सरकार की कंपनियां/निगम, राज्य सरकारें, राज्य सरकार की कंपनियां/निगम और वित्तीय संस्थान आदि शामिल हैं।*

चार्ट I.I: सरकारी कंपनियों और निगमों में इक्विटी में धारिता

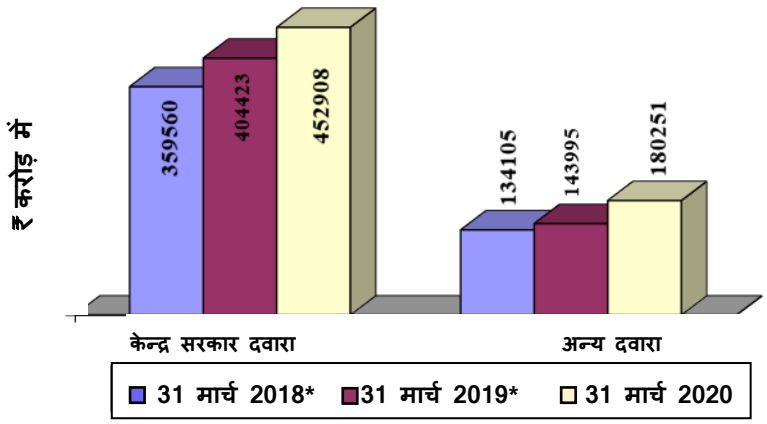

*(*2019-20 के दौरान, पिछले वर्ष के आंकड़े अपडेट किए गए क्योंकि उस वर्ष के लेखे प्राप्त हुए थे)*

सीपीएसई की प्रदत्त पूंजी में 2019-20 के दौरान केंद्र सरकार द्वारा किए गए ₹ 2,000 करोड़ से अधिक का निवेश का विवरण तालिका 1.3 में दिया गया है:

तालिका 1.3: केंद्र सरकार द्वारा किए गए ₹ 2,000 करोड़ से अधिक के निवेश

(₹ करोड़ में)

सीपीएसई का नाम	मंत्रालय का नाम	राशि
सांविधिक निगम		
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण	सड़क परिवहन और राजमार्ग	25,381
सरकारी कंपनियाँ		
इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड	वित्त	5,798
नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	रेलवे	5,100
डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन लिमिटेड	रेलवे	3,308
भारतीय रेलवे वित्त निगम लिमिटेड	रेलवे	2,500
नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	वित्त	2,400
उच्च शिक्षा वित्तपोषण एजेंसी	वित्त	2,100

1.2.2 सरकारी कंपनियों और निगमों को दिया गया ऋण

1.2.2.1 31 मार्च 2020 को बकाया दीर्घकालिक ऋण की गणना

31 मार्च 2020 को 427 सरकारी कंपनियों और निगमों में से 185 सीपीएसई में सभी स्रोतों से बकाया कुल दीर्घकालिक ऋण, ₹ 22,66,674 करोड़ था। 2019-20 के दौरान, सरकारी कंपनियों और निगमों के दीर्घकालिक ऋणों ने ₹ 4,60,384 करोड़ की वृद्धि दर्ज की। 31 मार्च 2020 को 185 सीपीएसई के कुल ऋणों में से, केंद्र सरकार से ऋण, ₹ 3,04,894 करोड़ था जिसमें से ₹ 22,742 करोड़ के ऋण 22 सीपीएसई में 2019-20 से संबंधित थे।

2018-19 के दौरान तथा साथ ही 2019-20 में इन 22 सीपीएसई में से 18 सीपीएसई[14] में दीर्घकालिक ऋणों में वृद्धि दर्ज की गई। दोनों वर्षों के दौरान 18 सीपीएसई में से, 11 सीपीएसई को ऋण दिया गया था। 10 सीपीएसई[15] को चालू परियोजनाओं के कार्यान्वयन के वित्तपोषण के लिए ऋण दिया गया था जबकि एक सीपीएसई (उत्तरी पूर्वी हस्तशिल्प और हथकरघा विकास निगम लिमिटेड) को कार्यशील पूंजीगत आवश्यकताओं तथा प्रशासनिक खर्चों के लिए ऋण दिया गया था, शेष सात सीपीएसई के मामले में, दीर्घकालिक ऋणों में वृद्धि ऋण के वास्तविक वितरण के कारण नहीं थी बल्कि पहले के ऋणों पर ब्याज के कारण हुई थी।

---

[14] *भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड, ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड, न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड, भारत गोल्ड माइंस लिमिटेड, कोलकाता मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड, नागपुर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड, बैंगलोर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड, मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड, एनएचपीसी लिमिटेड, इंडिया रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड, नेशनल बाइसिकल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, दामोदर वैली कॉरपोरेशन, चेन्नई मेट्रो रेल लिमिटेड, कोच्चि मेट्रो रेल लिमिटेड, नॉर्थ ईस्टर्न हैंडीक्राफ्टस एंड हैंडलूम डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कंपनी लिमिटेड।*

[15] *भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड, न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड, कोलकाता मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड, नागपुर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड, बैंगलोर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड, एनएचपीसी लिमिटेड, दामोदर वैली कॉरपोरेशन, चेन्नई मेट्रो रेल लिमिटेड।*

लेखापरीक्षा में पाया गया कि 18 में से 17 सीपीएसई ने 2019-20 के दौरान ऋण की मूलराशि/ऋण पर ब्याज चुकाया नहीं गया था जबकि एक सीपीएसई (न्यूक्लियर पॉवर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड) ने 2019-20 के दौरान ₹ 730 करोड़ के ऋण का भुगतान किया था।

सरकारी कम्पनियों तथा निगमों के बकाया दीर्घकालिन ऋणों का वर्षवार विवरण (केंद्र सरकार और अन्य[16] द्वारा) चार्ट 1.2 में दर्शाया गया है।

चार्ट 1.2: सरकारी कंपनियों और निगमों में बकाया दीर्घकालीन ऋण

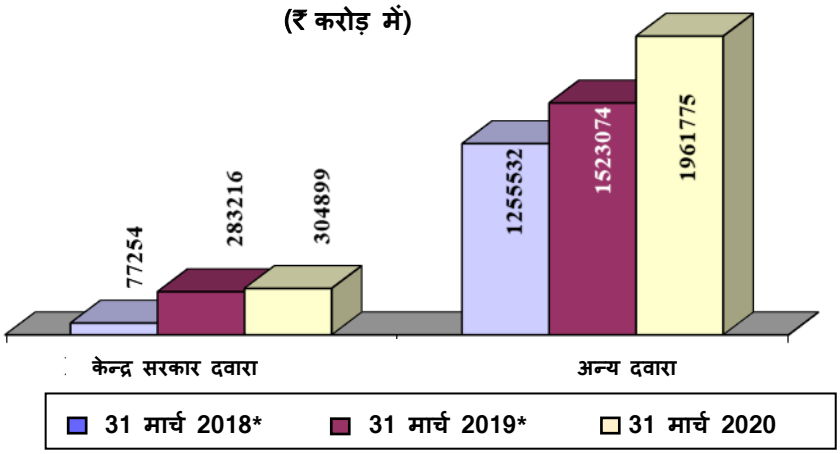

(* पिछले वर्षों के आंकड़े 2019-20 के दौरान अपडेट किए गए जब उस वर्ष के लेखा प्राप्त हुए थे)

427 सीपीएसई में से, 242 सीपीएसई (एक वैधानिक निगम यानी केंद्रीय भंडारण निगम सहित) में 31 मार्च 2020 तक कोई दीर्घकालिक ऋण नहीं था।

1.2.2.2 ऋण देनदारियों को पूरा करने के लिए परिसंपत्ति की पर्याप्तता

कुल परिसंपत्तियों के प्रति कुल ऋण का अनुपात यह निर्धारित करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक तरीका है कि क्या कंपनी विलायक रह सकती है। विलायक माना जाने के लिए, एक इकाई की परिसंपत्ति का मूल्य उसके ऋण/कर्ज़ की राशि से अधिक

[16] *अन्य में केंद्र सरकार की कंपनियां/निगम, राज्य सरकारें, राज्य सरकार की कंपनियां/निगम और वित्तीय संस्थान आदि शामिल हैं।*

होना चाहिए। 185 सीपीएसई में कुल परिसंपत्तियों के मूल्य पर दीर्घकालिक ऋणों का कवरेज, जिनके पास 31 मार्च 2020 तक बकाया ऋण था, तालिका 1.4 में दिया गया है।

तालिका 1.4: कुल परिसंपत्ति के साथ दीर्घकालिक ऋण की कवरेज

	सकारात्मक कवरेज				नकारात्मक कवरेज			
	सीपीएसई की संख्या	लंबी अवधि के ऋण	परिसंपत्ति	ऋण के प्रति परिसंपत्ति का प्रतिशत	सीपीएसई की संख्या	लंबी अवधि के ऋण	परिसंपत्ति	ऋण के प्रति परिसंपत्ति का प्रतिशत
		(₹ करोड़ में)				(₹ करोड़ में)		
सांविधिक निगम	5	4,27,064	8,50,614	199.18				
सूचीबद्ध कम्पनियां	38	11,60,424	27,59,587	237.81	1	238	87	36.55
असूचीबद्ध कंपनियाँ	122	6,56,203	13,78,399	210.06	19	22,745	4,290	18.86
कुल	**165**	**22,43,691**	**49,88,600**		**20**	**22,983**	**4,377**	

185 सीपीएसई में से, 20 सीपीएसई (परिशिष्ट-III) के संबंध में कुल परिसंपत्ति का मूल्य बकाया ऋण से कम था।

1.2.2.3 ब्याज कवरेज अनुपात

ब्याज कवरेज अनुपात (आईसीआर), का उपयोग किसी कंपनी की बकाया ऋण पर ब्याज का भुगतान करने की क्षमता निर्धारित करने के लिए किया जाता है और इसकी गणना ब्याज और करों से पूर्व कंपनी की आय (ईबीआईटी) को उसी अवधि के ब्याज खर्चों से विभाजित करके की जाती है। जितना अनुपात कम होगा, उतना ही कंपनी की ऋण पर ब्याज का भुगतान करने की क्षमता कम होती है। एक से नीचे आईसीआर होना संकेत देता था कि कंपनी ब्याज पर अपने खर्चों को पूरा करने के लिए पर्याप्त राजस्व अर्जन नहीं कर रही थी। सीपीएसई के सकारात्मक और नकारात्मक ब्याज कवरेज अनुपात का विवरण, जिसमें 2017-18 से 2019-20 की अवधि के दौरान बकाया ऋण थे, तालिका 1.5 में दिए गए हैं:

तालिका 1.5: ब्याज कवरेज अनुपात

वर्ष	ब्याज (₹ करोड़ में)	ब्याज और कर से पहले की आय (ईबीआईटी) (₹ करोड़ में)	सीपीएसई की संख्या	आईसीआर > = 1 वाले सीपीएसई की संख्या	आईसीआर < = 1 वाले सीपीएसई की संख्या
सांविधिक निगम					
2017-18	11,833.26	14,812.69	5	2	3
2018-19	2,774.34	4,773.15	5	1	4
2019-20	2,842.59	(-)42,389.9	5	2	3
सूचीबद्ध सरकारी कम्पनियां					
2017-18	63,824.23	1,80,205.34	39	29	10
2018-19	69,154.74	1,79,614.90	39	31	8
2019-20	45,061.56	1,30,174.92	39	25	14
असूचीबद्ध सरकारी कंपनियाँ					
2017-18	20,836.30	21,481.70	123	54	69
2018-19	24,420.86	17,699.80	128	52	76
2019-20	28,633.39	4,689.75	141	48	93

यह देखा गया कि पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2019-20 के दौरान, सूचीबद्ध तथा असूचीबद्ध सरकारी कंपनियों के मामले में एक बराबर या इससे अधिक के आईसीआर वाले सीपीएसई की संख्या में कमी हुई है। आठ सीपीएसई[17] के संबंध में, दीर्घकालिक ऋण पर देय ब्याज, 31 मार्च 2020 को उनकी कुल परिसंपत्ति के मूल्य से अधिक था जो इन कंपनियों में दिवालिया होने के उच्च जोखिम का संकेत देता है।

[17] *मणिपुर स्टेट ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, भारत गोल्ड माइन्स लिमिटेड, इरकॉन शिव पुरी गूना गण लिमिटेड, नेशनल बाइसिकल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, टीसीआईएल बीना टोल रोड लिमिटेड, अंडमान फिशरीज लिमिटेड, टीसीआईएल एलटीआर लिमिटेड, बर्डस जूट एंड एक्सपोर्टस लिमिटेड।*

1.2.2.4 केंद्र सरकार के ऋणों पर बकाया ब्याज की अवधि-वार विश्लेषण

31 मार्च 2020 तक, केंद्र सरकार द्वारा प्रदान किए गए 15 सीपीएसई के दीर्घकालिक ऋणों पर, ₹ 6110.42 करोड़ की ब्याज की राशि बकाया थी। सीपीएसई में केंद्र सरकार के ऋणों पर बकाया ब्याज का अवधि वार विश्लेषण तालिका 1.6 में दर्शाया गया है।

तालिका 1.6: केंद्र सरकार के ऋणों पर बकाया ब्याज

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	सीपीएसई का नाम	केंद्र सरकार के ऋणों पर बकाया ब्याज	1 वर्ष से कम के लिए बकाया केंद्र सरकार के ऋण पर ब्याज	1 - 3 वर्षों के लिए बकाया केंद्र सरकार के ऋण पर बकाया ब्याज	3 वर्षों से अधिक के लिए बकाया केंद्र सरकार के ऋणों पर ब्याज
1	बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड	86.22	0.59	20.32	65.31
2	भारत पंप्स एंड कंप्रेसरस लिमिटेड	52.70	17.37	35.33	0.00
3	बर्ड्स जूट एंड एक्सपोर्ट्स लिमिटेड	63.05	3.84	11.48	47.73
4	सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	123.85	0.00	0.00	123.85
5	हैवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड	48.13	10.53	27.45	10.15
6	हिंदुस्तान कीटनाशक लिमिटेड	32.96	4.70	14.09	14.17
7	एचएमटी मशीन टूल्स	262.96	58.61	158.15	46.20

	लिमिटेड				
8	**हिंदुस्तान साल्ट्स लिमिटेड**	23.35	4.00	11.06	8.29
9	**एनईपीए लिमिटेड**	165.65	26.81	138.84	0.00
10	**एनएचपीसी लिमिटेड**	69.71	69.71	0.00	0.00
11	**डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन लिमिटेड**	2,182.50	966.98	864.19	351.33
12	**फर्टिलाइजर एंड केमिकल्स त्रावणकोर लिमिटेड**	717.05	239.02	478.03	0.00
13	**भारत गोल्ड माइंस लिमिटेड**	1500.10	127.61	125.11	1,247.38
14	**हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड**	244.68	56.02	103.92	84.74
15	**नेशनल टेक्सटाइल कॉरपोरेशन लिमिटेड**	537.51	46.84	140.51	350.16
	कुल	**6,110.42**	**1,632.63**	**2,128.48**	**2,349.31**

1.2.3 सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनियों में निवेश

वर्ष 2019-20 के दौरान केन्द्र सरकार/राज्य सरकार और केन्द्र/राज्य सरकार की कम्पनियों/निगमों द्वारा 180 सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कम्पनियों[18] में निवेश की गई पूंजी को चार्ट 1.3 में दर्शाया गया है।

चार्ट 1.3: सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनियों में शेयर पूंजी की संरचना

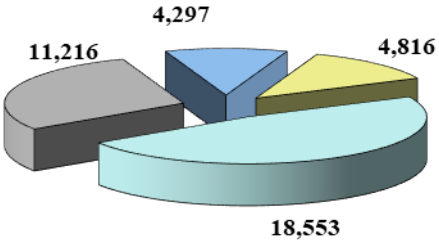

₹ करोड़ में

केन्द्र सरकार, केन्द्र सरकार की कंपनियाँ और निगम - ₹ 18,553 करोड़

राज्य सरकार, राज्य सरकार की कंपनियाँ और निगम - ₹ 4,816 करोड़

वित्तीय संस्थाएं और बैंक - ₹ 11,216 करोड़

अन्य - ₹ 4,297 करोड़

31 मार्च 2020 तक, सरकार द्वारा नियंत्रित इन अन्य कंपनियों में इक्विटी ₹ 38,882 करोड़ थी। सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनियों की इक्विटी में 2019-20 में ₹ 1,937 करोड़ की वृद्धि हुई।

1.2.4 सरकारी कंपनियों में इक्विटी निवेश का बाजार पूंजीकरण

बाजार पूंजीकरण, उन कंपनियों के शेयरों के बाजार मूल्य का घोतक है जिनके शेयर सूचीबद्ध हैं। 31 मार्च 2020 तक, 70 सरकारी कंपनियों के शेयरों में, जो की भारत के विभिन्न स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध थीं, 56 सरकारी कंपनियों के शेयर शामिल थे, जिनमें दो नई सूचीबद्ध सरकारी कंपनियाँ[19], सरकारी कंपनियों की सात सहायक कंपनियाँ[20] और सात सरकारी नियंत्रित अन्य कंपनियाँ[21] थीं।

---

[18] 203-23 सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनियाँ जिनके लेखे तीन साल या उससे अधिक के लिए बकाया थे या निष्क्रिय/परिसमापन के अधीन थे या पहले लेखे देय नहीं थे।

[19] इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड, रेल विकास निगम लिमिटेड।

54 सूचीबद्ध सरकारी कंपनियों (56-2 नई सूचीबद्ध सरकारी कंपनियों) के संबंध में, 2019-20 के दौरान 52 कंपनियों के शेयरों का कारोबार किया गया था और दो कंपनियों[22] के शेयरों का कारोबार नहीं किया गया था। सरकारी कंपनियों की सात सहायक कंपनियों के संबंध में, छह के शेयरों का कारोबार किया गया और एक सहायक कम्पनी ईस्टर्न इन्वेस्टमेंट लिमिटेड के शेयरों का कारोबार नहीं किया गया।

31 मार्च 2019 तक ₹ 14,41,435 करोड़ की तुलना में 31 मार्च 2020 को 58 कारोबार वाली सूचीबद्ध सरकारी कंपनियों[23] (सात सहायक कंपनियों सहित) के शेयरों का कुल बाजार मूल्य ₹ 8,39,970 करोड़ (इक्विटी निवेश ₹ 88,194 करोड़) रहा है। इन 58 सीपीएसई के शेयरों का कुल बाजार मूल्य 31 मार्च 2020 को ₹ 6,01,465 करोड़ (41.73 प्रतिशत) से घटा था। अधिकतम बाजार पूंजीकरण के साथ शीर्ष तीन क्षेत्रों में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस (₹ 3,14,073 करोड़), विद्युत् (₹ 2,36,525 करोड़) और कोयला (₹ 92,379 करोड़) थे। किसी भी क्षेत्र में शेयरों के बाजार मूल्य में वृद्धि नहीं देखी गई जबकी शेयरों के बाजार मूल्य में उच्चतम कमी शहरी विकास क्षेत्र (75.34 प्रतिशत) में पाई गई, इसके बाद भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम क्षेत्र (70.22 प्रतिशत) तथा वाणिज्य और उद्योग क्षेत्र (59.42 प्रतिशत) थे। 31 मार्च 2020 तक, 52 सूचीबद्ध सरकारी कंपनियों (छह सहायक कंपनियों को छोड़कर) के शेयरों का बाजार मूल्य ₹ 7,87,152 करोड़ था, जिसमें से केंद्र सरकार के पास मौजूद शेयरों का बाजार मूल्य ₹ 4,75,542 करोड़ था।

---

[20] *बामर लॉरी एंड कंपनी लिमिटेड, चेन्नई पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, हिंदुस्तान फ्लोरोकार्बन्स लिमिटेड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड, ईस्टर्न इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड।*

[21] *ड्रेजिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, इंडबैंक मर्चेंट बैंकिंग सर्विसेज लिमिटेड, बिसरा स्टोन लाइम कंपनी लिमिटेड, तमिलनाडु टेलीकम्युनिकेशन लिमिटेड, इंडबैंक हाउसिंग लिमिटेड, उड़ीसा मिनरल्स डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड, पीएनबी गिल्ट्स लिमिटेड।*

[22] *दुस्तान केबल्स लिमिटेड, हिंदुस्तान फोटो-फिल्म्स (मैन्युफैक्चरिंग) कंपनी लिमिटेड।*

[23] *58 = 52 सूचीबद्ध कारोबारी सरकारी कंपनियाँ + 6 सूचीबद्ध कारोबारी सहायक सरकारी कंपनियाँ।*

इस अवधि के दौरान, एस एंड पी बीएसई सूचकांक[24] 31 मार्च 2019 को 38,672.91 से 23.80 प्रतिशत घटकर 31 मार्च 2020 तक 29,468.49 हो गया। एस एंड पी बीएसई - सीपीएसई सूचकांक[25] 31 मार्च 2019 को 1468.92 से 30.70 प्रतिशत घटकर 31 मार्च 2020 तक 885.74 हो गया।

पिछले पांच वर्षों के लिए कारोबार वाली सूचीबद्ध सीपीएसई के बाजार पूंजीकरण की प्रवृत्ति को एस एंड पी बीएसई सेंसेक्स और एसएंडपी बीएसई-सीपीएसई सूचकांक की तुलना में चार्ट-1.4 में दर्शाया गया है।

चार्ट-1.4: बीएसई सेंसेक्स और सीपीएसई सूचकांक की तुलना में बाजार पूंजीकरण की प्रवृत्ति

एसएंडपी बीएसई सेंसेक्स और एसएंडपी सीपीएसई सूचकांक

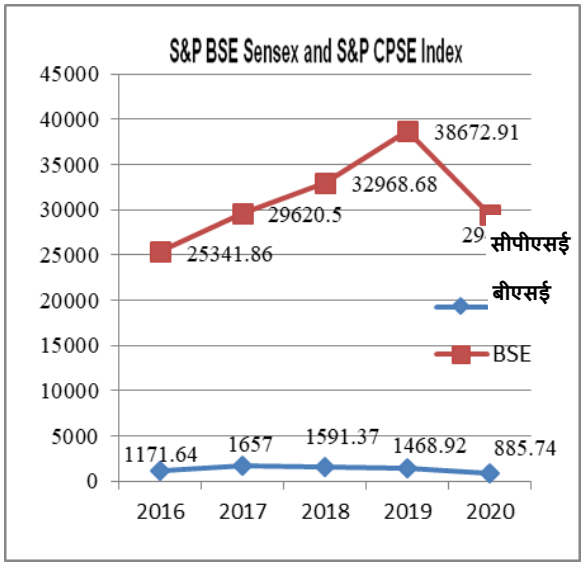

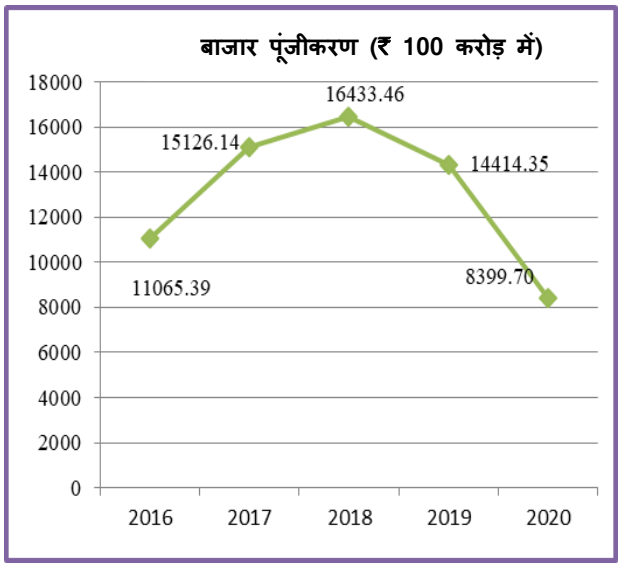

यह देखा गया कि 2015-16 से 2017-18 के दौरान कारोबार वाली सूचीबद्ध सीपीएसई की बाजार पूंजीकरण की प्रवृत्ति समान थी, जब इनकी तुलना एसएंडपी बीएसई सेंसेक्स और एसएंडपी सीपीएसई सूचकांक से की गई। 2018-19 में, इन सीपीएसई के शेयरों का बाजार मूल्य 12.29 *प्रतिशत* (₹ 16,43,346 करोड़ से ₹ 14,41,435 करोड़ तक) घट गया, जब एसएंडपी बीएसई सेंसेक्स में 17.30 *प्रतिशत* (32,968.68 से 38,672.91) की वृद्धि हुई थी।

---

[24] *एसएंडपी बीएसई सेंसेक्स 30 घटक शेयरों का बेंचमार्क इंडेक्स है जो बड़ी, लिक्विड और रिप्रेजेंटेटिव कंपनियों के सैंपल का प्रतिनिधित्व करता है।*

[25] *एसएंडपी बीएसई सीपीएसई सूचकांक बीएसई में सूचीबद्ध सीपीएसई के प्रदर्शन को मापता है।*

हालांकि, इसी अवधि के दौरान एसएंडपी सीपीएसई सूचकांक 7.69 प्रतिशत (1,591.37 से 1,468.92) घट गया। 2019-20 में, दोनों सूचकांको में बाजार पूंजीकरण में गिरावट की प्रवृति देखी गई।

छह सहायक सरकारी कंपनियों के शेयरों का बाजार मूल्य, जिनके शेयरों का कारोबार 2019-20 के दौरान किया गया था, 31 मार्च 2020 तक ₹ 52,818 करोड़ पर था। 31 मार्च 2019 की तुलना में 31 मार्च 2020 तक, छह सहायक सरकारी कंपनियों में शेयरों का कुल बाजार मूल्य ₹ 39,834 करोड़ कम हो गया था।

31 मार्च 2020 को, उच्चतम बाजार पूंजीकरण के साथ शीर्ष 10 सीपीएसई को तालिका 1.7 में दर्शाया गया है:

तालिका 1.7: उच्चतम बाजार पूंजीकरण के साथ सीपीएसई

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	सीपीएसई का नाम	बाज़ार पूंजीकरण
1	कोल इंडिया लिमिटेड	86,278
2	तेल और प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड	85,923
3	एनटीपीसी लिमिटेड	83,312
4	पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	83,182
5	इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	76,867
6	भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड	68,559
7	गेल (इंडिया) लिमिटेड	34,676
8	हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड	28,975
9	एनएमडीसी लिमिटेड	24,495
10	पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड	24,328

31 मार्च 2020 तक 58 सूचीबद्ध सरकारी कंपनियों में से तीन सीपीएसई के संबंध में बाजार पूंजीकरण में वृद्धि हुई थी। बाजार पूंजीकरण में वृद्धि के साथ सीपीएसई को तालिका 1.8 में दर्शाया गया है:

तालिका 1.8: 31 मार्च 2020 तक बाजार पूंजीकरण में वृद्धि के साथ सीपीएसई

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	सीपीएसई का नाम	31 मार्च 2019 को बाजार पूंजीकरण	31 मार्च 2020 को बाजार पूंजीकरण	पूंजीकरण में अंतर
1	राइट्स लिमिटेड	5,181.00	6,148.75	967.75
2	मिश्र धातु निगम लिमिटेड	2,642.43	3,350.58	708.15
3	गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड	1,116.31	1,568.79	452.48

1.3 सीपीएसई से प्रतिफल

1.3.1 सीपीएसई द्वारा अर्जित लाभ

2018-19 में 233 की तुलना में 2019-20 में लाभ अर्जित करने वाले सरकारी कम्पनियों तथा निगमों की संख्या 224 थी (23 सीपीएसई शामिल किए गए और 32 सीपीएसई को छोड़ दिया गया)। इन 23 सीपीएसई *(परिशिष्ट-IV)* में से तीन सीपीएसई नई थी तथा उनके संचालन के प्रथम वर्ष में लाभ प्राप्ति हुई तथा 20 सीपीएसई ने पिछले वर्ष में निवल हानि उठाने के बाद लाभ कमाया। 20 में से केवल आठ सीपीएसई ने संचालन लाभ[26] के कारण लाभ अर्जित किया। 32 सीपीएसई *(परिशिष्ट-V)* जिन्हे पिछले वर्ष में लाभ कमाने के बाद हानि हुई, 27 सीपीएसई को मुख्यत: संचालन हानि के कारण हानि हुई।

2018-19 में ₹ 1,77,758 करोड़ का अर्जित लाभ 2019-20 में घटकर ₹ 1,40,976 करोड़ हो गया। तदनुसार, सीपीएसई का इक्विटि पर रिटर्न (आरओई) 2018-19 में 233 सीपीएसई के 18.69 प्रतिशत की तुलना में 2019-20 में 224 सीपीएसई का 15.31

[26] *अन्य आय से खर्चों को घटाकर को छोड़कर कुल आय।*

प्रतिशत था। 2019-20 में 425 सरकारी कंपनियों और निगमों[27] में आरओई 7.53 प्रतिशत था जिसमें घाटे में चल रही 181 तथा 22 शून्य लाभ/हानि वाली कम्पनियां सम्मिलित थी। 2017-18 से 2019-20 की अवधि के दौरान लाभ अर्जित करने वाले सीपीएसई की संख्या को चार्ट-1.5 में दर्शाया गया है।

चार्ट-1.5: लाभ कमाने वाले सीपीएसई की संख्या

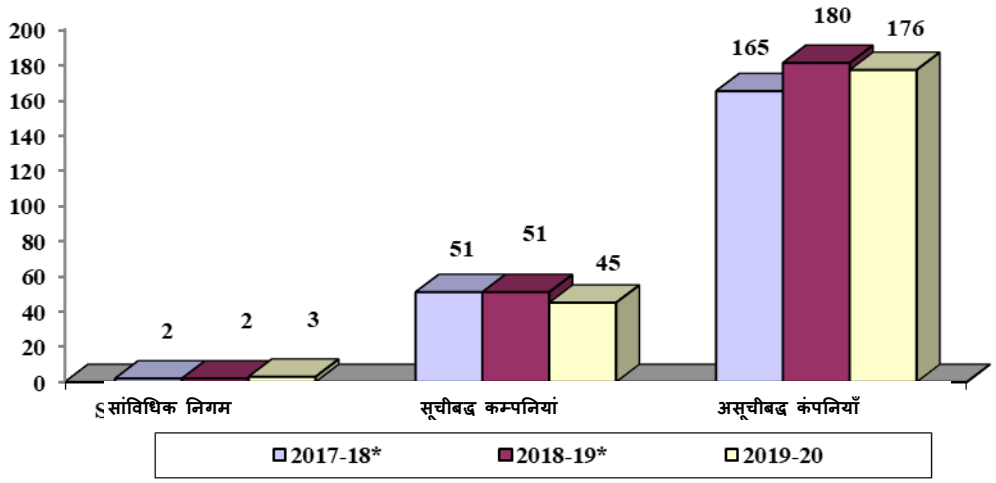

(* पिछले वर्षों के आंकड़े 2019-20 के दौरान अपडेट किए गए, जब उस वर्ष के लेखा प्राप्त हुए थे)

2019-20 के दौरान अधिकतम लाभ अर्जित करने वाले शीर्ष तीन क्षेत्रों का विवरण तालिका 1.9 में संक्षेप में प्रस्तुत किया गया है:

तालिका 1.9: शीर्ष 3 क्षेत्र जिन्होंने वर्ष 2019-20 के दौरान अधिकतम लाभ में योगदान दिया

क्षेत्र	लाभ कमाने वाले सीपीएसई की संख्या	अर्जित निवल लाभ (₹ करोड़ में)	कुल सीपीएसई लाभ के प्रति लाभ का प्रतिशत
विद्युत			
सूचीबद्ध सरकारी कंपनियाँ	4	25,583	18.14

[27] *भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण को छोड़कर जिन्हें शून्य लाभ/हानि सीपीएसई माना गया है क्योंकि उनके नुकसान को समायोजित किया जाता है जो फुटनोट 4 में दिया है।*

असूचीबद्ध सरकारी कंपनियाँ	33	7,763	5.51
सांविधिक निगम	1	185	0.13
उप-जोड़ (क)	38	33,531	23.78
पेट्रोलियम			
सूचीबद्ध सरकारी कंपनियाँ	6	29,283	20.77
असूचीबद्ध सरकारी कंपनियाँ	8	2,904	2.06
उप- जोड़ (ख)	14	32,187	22.83
कोयला और लिग्नाइट			
सूचीबद्ध सरकारी कंपनियाँ	2	12,695	9.00
असूचीबद्ध सरकारी कंपनियाँ	6	16,898	11.98
उप-जोड़ (ग)	8	29,593	20.98
जोड़ (क+ख+ग)	**60**	**95,311**	**67.61**

इन तीन क्षेत्रों में 2018-19 के दौरान 60 सीपीएसई के द्वारा 73.06 प्रतिशत योगदान की तुलना में 2019-20 के दौरान, सीपीएसई के कुल लाभ का 67.61 प्रतिशत का ₹ 95,311 करोड़ का निवल लाभ 60 सीपीएसई के द्वारा योगदान दिया गया था।

29 सीपीएसई द्वारा ₹ 41,472 करोड़ के शुद्ध लाभ का योगदान दिया गया था जो रक्षा, कोयला, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष क्षेत्रों में कार्यरत था जो बाजार की प्रतिस्पर्धा के लिए खुले नहीं थे। यह 2019-20 के दौरान, सभी 224 सीपीएसई में ₹ 1,40,976 करोड़ के कुल लाभ का 29.42 प्रतिशत था। वर्ष 2019-20 में इन 29 सीपीएसई का आरओई 42.29 प्रतिशत था, जो प्रतिस्पर्धी माहौल में कार्य करने वाले 195 सीपीएसई में 12.09 प्रतिशत की तुलना में था।

वर्ष 2019-20 के दौरान ₹ 5,000 करोड़ से अधिक का लाभ अर्जित करने वाले सीपीएसई की सूची तालिका 1.10 में दर्शायी गई है:

तालिका 1.10: सीपीएसई की सूची, जिसने ₹ 5,000 करोड़ से अधिक का लाभ अर्जित किया

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	सीपीएसई का नाम	निवल लाभ
1	तेल और प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड	13,445
2	कोल इंडिया लिमिटेड	11,281
3	पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	10,811
4	एनटीपीसी लिमिटेड	10,113
5	गेल (इंडिया) लिमिटेड	6,621
6	महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड	6,427
7	पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड	5,655
कुल		**64,353**

यह देखा जा सकता है कि 2019-20 के दौरान इन सात सीपीएसई ने 224 सीपीएसई द्वारा अर्जित कुल लाभ का 45.65 प्रतिशत योगदान दिया।

180 सरकारी नियंत्रित अन्य कंपनियों में से 124 सीपीएसई ने 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के दौरान ₹ 10,369 करोड़ का लाभ कमाया जो 2018-19 में ऐसे 123 सीपीएसई द्वारा अर्जित ₹ 9,111 करोड़ के लाभ की तुलना में ₹ 1,285 करोड़ (13.81 प्रतिशत) की वृद्धि थी। तदनुसार, 2018-19 में 123 सीपीएसई का 20.33 प्रतिशत की तुलना में 2019-20 में 124 सीपीएसई का आरओई 21.92 प्रतिशत था, सभी 180 सरकारी नियंत्रित अन्य कंपनियों में आरओई 2019-20 में 19.26 प्रतिशत था।

सरकारी कंपनियों द्वारा अर्जित लाभ 2019-20 के दौरान ₹ 36,782 करोड़ (20.69 प्रतिशत) घटा जो 2018-19 में ₹ 1,77,758 करोड़ से घट कर 2019-20 में ₹ 1,40,976 करोड़ हो गया, जबकि सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कम्पनियों द्वारा अर्जित लाभ 2019-

20 में ₹ 1,258 करोड़ (13.81 प्रतिशत) बढ़ा जो, 2018-19 में ₹ 9,111 करोड़ से बढ़कर 2019-20 में ₹ 10,369 करोड़ हो गया।

1.3.2 हानि उठाने वाली सीपीएसई

वर्ष 2019-20 के दौरान, 181 सरकार कंपनियों तथा निगमों ने हानियाँ उठाई। घाटे में चल रही इन 181 सीपीएसई में से 115 सीपीएसई को पिछले पांच वर्षों में 3 से 5 वर्ष तक घाटा हुआ है जबकि 64 सीपीएसई को 5 वर्षों से लगातार घाटा हुआ है। 2019-20 में, इन सीपीएसई द्वारा उठाई गई हानि बढ़कर ₹ 68,434 करोड़ हो गई, जोकि 2018-19 के दौरान ₹ 40,835 करोड़ थी, जैसा कि तालिका 1.11 में दर्शाया गया है।

तालिका 1.11: 2017-18 से 2019-20 के दौरान, हानि उठाने वाले सीपीएसई की संख्या

सूचीबद्ध/असूचीबद्ध वर्ष	हानि वाले सीपएसई की संख्या	वर्ष के लिए निवल हानि (₹ करोड़ में)	संचित हानि (₹ करोड़ में)	निवल मूल्य[28] (₹ करोड़ में)
सांविधिक निगम				
2017-18	1	847	0	12,144
2018-19	1	1,115	0	11,370
2019-20	0	0	0	0
सूचीबद्ध सरकारी कंपनियाँ				
2017-18	12	8,292	40,433	9,146
2018-19	12	5,476	35,149	-18,946
2019-20	18	11,987	39,239	1,20,571
असूचीबद्ध सरकारी कंपनियाँ				
2017-18	130	31,630	89,907	1,33,517
2018-19	136	34,244	90,883	1,10,680
2019-20	163	56,447	1,15,821	1,31,406
जोड़				
2017-18	**143**	**40,769**	**1,30,340**	**1,54,807**
2018-19	**149**	**40,835**	**1,26,032**	**1,03,104**
2019-20	**181**	**68,434**	**1,55,060**	**2,51,977**

[28]निवल मूल्य का अर्थ है कि भुगतान की गई शेयर पूंजी और मुफ्त भंडार और अधिशेष कम संचित हानि और आस्थगित राजस्व व्यय का कुल योग। नि: शुल्क भंडार का अर्थ है कि सभी लाभ और प्रीमियम खाता से बने भंडार, लेकिन परिसंपत्तियों के पुनर्मूल्यांकन से बनाए गए भंडार को शामिल न करें और मूल्यह्रास प्रावधान वापस लिखें।

2019-20 में 181 सीपीएसई द्वारा किए गए ₹ 68,434 करोड़ की कुल हानि में से, 21 सीपीएसई द्वारा ₹ 2,527 करोड़ की हानि का योगदान दिया गया था, जो बाजार की प्रतिस्पर्धा के लिए खुले नहीं थे। वर्ष 2019-20 के दौरान, तालिका 1.12 में सूचीबद्ध सीपीएसई को ₹ 1,000 करोड़ से अधिक की हानि हुई।

तालिका 1.12: सीपीएसई जो 2019-20 के दौरान ₹ 1,000 करोड़ से अधिक की हानि उठाती है

(₹ करोड़ में)

क्रम.सं.	सीपीएसई का नाम	शुद्ध हानि
1	भारत संचार निगम लिमिटेड	15,500
2	एयर इंडिया लिमिटेड	7,766
3	ओएनजीसी विदेश लिमिटेड	7,264
4	नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	4,111
5	राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड	3,910
6	महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड	3,696
7	लैंकोटीस्टा हाइड्रो पावर लिमिटेड	2,956
8	मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड	2,708
9	ओएनजीसी पेट्रो एडिशन लिमिटेड	2,090
10	चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2,078
11	ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	1,524
12	यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	1,486
13	भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड	1,473
14	ओएनजीसी-मैंगलोर पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड	1,400

वर्ष 2019-20 के दौरान, सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य 180 कंपनियों में से 56 कंपनियों को ₹ 1,407 करोड़ कि हानि हुई जो 2018-19 में ऐसी 55 सीपीएसई द्वारा उठाई गई हानि ₹ 2,387 करोड़ की तुलना में ₹ 980 करोड़ (41.06 प्रतिशत) कम थी।

1.3.3 सरकारी कंपनियों में पूंजी का क्षरण

31 मार्च 2020 तक ₹ 1,74,596 करोड़ की संचित हानि के साथ 188 सरकारी कम्पनियां[29] थी। 188 सीपीएसई में से, 140 सीपीएसई को वर्ष 2019-20 में ₹ 22,203 करोड़ का हानि हुई, 48 सीपीएसई को वर्ष 2019-20 में हानि (शून्य लाभ सहित) नहीं हुई, भले ही उन्हें ₹ 19,536 करोड़ की संचित हानि हुई हो। 188 सीपीएसई में से 33 का समापन/बंद/परिसमापन/नीतिगत विनिवेश के तहत हुआ।

188 सीपीएसई में से 90 का निवल मूल्य, संचित हानि से पूरी तरह से क्षय हो गया था और उनका निवल मूल्य या तो शून्य या नकारात्मक था। इन 90 सीपीएसई का निवल मूल्य, 31 मार्च 2020 तक इन सीपीएसई में ₹ 49,422 करोड़ के इक्विटी निवेश के मुकाबले (-) ₹ 1,15,829 करोड़ था। इसमें सात सूचीबद्ध कंपनियाँ शामिल थीं, जिनकी कुल संपत्ति ₹ 6592 करोड़ के इक्विटी निवेश के मुकाबले (-) ₹ 39,008 करोड़ थी। 90 सीपीएसई में से, जिनकी पूंजी (शून्य या ऋणात्मक निवल मूल्य होने के नाते) समाप्त हो गई थी, 13 सीपीएसई ने वर्ष 2019-20 के दौरान, ₹ 1,713 करोड़ का लाभ अर्जित किया था (परिशिष्ट-VI)।

90 सीपीएसई में से 17 में, जिनकी पूंजी क्षीण हो गई थी, 31 मार्च 2020 तक बकाया सरकारी ऋण ₹ 6,045 करोड़ था। इसमें ₹ 937 करोड़ के बकाया सरकारी ऋण वाली दो सूचीबद्ध कंपनियाँ शामिल थी।

निवल मूल्य 334 सीपीएसई में से 29 के संबंध में उनकी प्रदत्त पूंजी के आधे से भी कम था, जिनकी निवल सम्पत्ति 31 मार्च 2020 के अंत में सकारात्मक थी, जो उनकी संभावित वित्तीय बिमारी का संकेतक है। कुल मिलाकर, सभी 427 सरकारी कंपनियों तथा निगमों का निवल मूल्य उनकी ₹ 6,33,159 करोड़ की प्रदत्त पूंजी के मुकाबले ₹ 16,36,946 करोड़ था।

---

[29] *भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और भारतीय अंत र्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण को छोड़कर जिन्हे शून्य लाभ/हानि सीपीएसई माना गया है क्योंकि उनकी हानि को फुटनोट 5 में दिए गए रूप में समायोजित किया जाता है।*

1.3.4 सीपीएसई द्वारा लाभांश भुगतान

सरकारी कंपनियों तथा निगमों द्वारा अर्जित लाभ और घोषित लाभांश का विवरण तालिका 1.13 में दिया गया है:

तालिका 1.13: अर्जित लाभ और घोषित लाभांश

श्रेणी	सीपीएसई का नाम	प्रदत्त पूंजी (₹ करोड़ में)	निवल लाभ (₹ करोड़ में)	घोषित लाभांश (₹ करोड़ में)
सांविधिक निगम	2	725	2,357	844
सूचीबद्ध कम्पनियां	37	75,364	93,821	55,627
असूचीबद्ध कंपनियाँ	60	49,175	32,593	17,016
जोड़	**99**	**1,25,264**	**1,28,771**	**73,487**

427 सरकारी कंपनियो तथा निगमों में से 99 सीपीएसई ने 2019-20 में लाभांश घोषित किया। इन 99 लाभ कमाने वाले सीपीएसई के शुद्ध लाभ के प्रतिशत के रूप में घोषित लाभांश 2018-19 में 44.01 प्रतिशत से बढ़कर 2019-20 में 57.07 प्रतिशत हो गया। निरपेक्ष रूप से, सीपीएसई द्वारा 2019-20 में घोषित लाभांश में पिछले वर्ष की तुलना में, ₹ 1,721 करोड़ की वृद्धि हुई। चार्ट-1.6 में घोषित लाभांश को दर्शाया गया है जो उन सीपीएसई के अर्जित निवल लाभ और प्रदत्त पूंजी की तुलना में जिन्होंने पिछले तीन वर्षों के दौरान लाभांश घोषित किया।

चार्ट 1.6 : अर्जित निवल लाभ और प्रदत्त पूंजी की तुलना में घोषित लाभांश (करोड़ ₹ में)

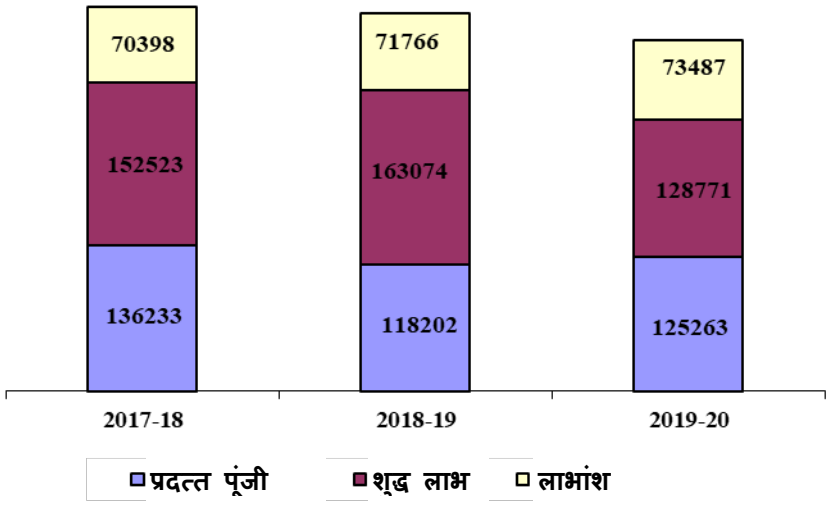

वर्ष 2019-20 के लिए 99 सीपीएसई द्वारा घोषित, ₹ 73,487 करोड़ के कुल लाभांश में से, केंद्र सरकार द्वारा प्राप्त/प्राप्य ₹ 79,680 करोड़ के इक्विटी निवेश वाले 68 सीपीएसई[30] में ₹ 34,944 करोड़ (₹ 54,890 करोड़ घोषित कुल लाभांश का 63.66 प्रतिशत), था। वर्ष 2018-19 के दौरान, 427 सीपीएसई की इक्विटी पूंजी में केंद्र सरकार द्वारा किए गए ₹ 4,52,908 करोड़ के कुल निवेश पर लाभांश के रूप में प्रतिफल 9.16 प्रतिशत की तुलना में 7.72 प्रतिशत था। इसी तरह, वर्ष 2019-20 में, 42 सीपीएसई को अन्य सीपीएसई में इक्विटी धारिता पर ₹ 17,792 करोड़ की प्रदत्त पूंजी पर लाभांश के रूप में ₹ 18,140 करोड़ प्राप्त हुए। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अधीन 13 सीपीएसई ने ₹ 26,349 करोड़ की लाभांश राशि घोषित की जो कि 2019-20 में 99 सीपीएसई द्वारा घोषित ₹ 73,487 करोड़ के कुल लाभांश का 35.86 प्रतिशत थी।

मई 2016 में, डीआईपीएएम द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देशों में यह परिकल्पना की गई थी कि प्रत्येक सीपीएसई, कर के बाद लाभ के न्यूनतम वार्षिक लाभांश का 30 प्रतिशत या निवल मूल्य के पांच प्रतिशत का भुगतान करेगा, जो भी अतिरिक्त कानूनी प्रावधानों के तहत अनुमत अधिकतम लाभांश के अधीन है। हालाँकि, 49 सरकारी कंपनियों (11 सूचीबद्ध

[30] *200 सीपीएसई में से 68 सीपीएसई (194 सरकारी कंपनियाँ + 6 सांविधिक निगम) जहां केन्द्र सरकार की प्रत्यक्ष होल्डिंग है।*

सीपीएसई सहित) ने सरकार द्वारा निर्धारित लाभांश की घोषणा नहीं की, जैसा कि अनुबंध-VII में दर्शाया गया है। 2019-20 में, इस आधार पर कुल कमी ₹ 11,488 करोड़ थी (वर्ष 2018-19 के दौरान 36 सरकारी कंपनियों द्वारा ₹ 8011 करोड़ की कमी)।

31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के दौरान, सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य 180 कंपनियों[31] में से 124 कंपनियों ने ₹ 10,369 करोड़ का लाभ अर्जित किया। इन 124 कंपनियों में से, 31 ने ₹ 1,077 करोड़ की लाभांश राशि घोषित की, जो उनकी ₹ 8,032 करोड़ की प्रदत्त पूंजी का 13.41 प्रतिशत थी। सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य 31 कंपनियों के क्षेत्रवार वर्गीकरण जिसने वर्ष 2019-20 के दौरान लाभांश घोषित किया था, को तालिका 1.14 में दर्शाया गया है:

तालिका 1.14: सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनियों द्वारा घोषित लाभांश

क्षेत्र	कंपनियों की संख्या	प्रदत्त पूंजी (₹ करोड़ में)	शुद्ध लाभ (₹ करोड़ में)	घोषित लाभांश (₹करोड़ में)
विद्युत्	6	5,490.29	1,191.8	523.08
वित्तीय सेवाएं	15	1,367.46	1,718.58	438.26
ठेका और निर्माण सेवाएँ	3	448	144.11	72.55
बीमा	2	474.46	471.01	24.79
परिवहन सेवाएं	1	164	41.43	13.12
ट्रेडिंग और मार्केटिंग	1	40.56	16.32	2.84
दूर संचार सेवाएं	1	47.24	82.36	2.53
औद्योगिक विकास और तकनीकी परामर्श	2	0.43	0.35	0.17
जोड़	**31**	**8,032.44**	**3,665.96**	**1,077.34**

[31] *203-23 सरकार नियंत्रित अन्य कंपनियाँ जिनके लेखे तीन वर्ष या उससे अधिक समय से बकाया थे या निष्क्रिय/परिसमापन के तहत थे या देय नहीं थे।*

1.4 सरकारी कम्पनियों और निगमों की प्रचालन दक्षता

1.4.1 उत्पादन का मूल्य

तीन वर्षों की अवधि के दौरान 427 सरकारी कम्पनियों और निगमों के उत्पादन का मूल्य, कुल परिसंपत्तियों तथा नियोजित पूंजी के सारांश को दर्शाने वाला सार चार्ट 1.7 में दिया गया है।

चार्ट 1.7: उत्पादन का मूल्य, परिसंपत्तियां तथा नियोजित पूंजी (₹ करोड़ में)

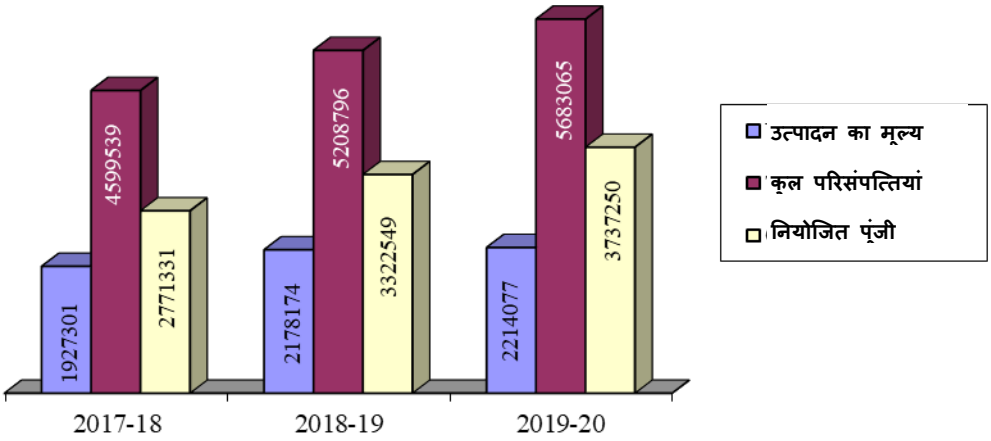

पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2019-20 में उत्पादन का मूल्य, कुल परिसंपत्ति तथा नियोजित पूंजी में वृद्धि हुई थी। उत्पादन का मूल्य, कुल परिसंपत्ति तथा नियोजित पूंजी का सीपीएसई वार विवरण परिशिष्ट-VIII में दिया गया हैं।

2019-20 को समाप्त हुए पिछले तीन वर्षों के एकाधिकार[32], और गैर एकाधिकार सीपीएसई के संबंध में उत्पादन, कुल परिसंपत्तियों तथा नियोजित पूंजी का मूल्य तालिका 1.15 में दिया गया है।

---

[32] *एकाधिकार का अर्थ है एक बाजार संरचना जो एक एकल विक्रेता की विशेषता वाली है, जो बाजार में एक अद्वितीय उत्पाद बेचती है। एकाधिकार बाजार में, विक्रेता को किसी प्रतिस्पर्धा का सामना नहीं करना पड़ता है, क्योंकि वह कोई करीबी विकल्प के साथ माल का एकमात्र विक्रेता है। यदि जिस भौगोलिक क्षेत्र में यह संचालित होता है, उस में कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है तो सीपीएसई को एकाधिकार के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। पेट्रोलियम क्षेत्र के अंतर्गत सीपीएसई को एकाधिकार श्रेणी में शामिल किया गया है क्योंकि पेट्रोलियम उत्पादों का मूल्य निर्धारण तंत्र प्रभावी रूप से सरकारी नियंत्रण में होता है, सरकार के स्वामित्व वाली और नियंत्रित पेट्रोलियम उत्पाद कंपनियाँ आभासी एकाधिकार के रूप में कार्य करती हैं।*

तालिका 1.15: एकाधिकार बनाम गैर-एकाधिकार के उत्पादन, परिसंपत्तियों तथा नियोजित पूंजी का मूल्य

(₹ करोड़ में)

टाइप/वर्ष	सीपीएसई की संख्या	उत्पादन का मूल्य	कुल परिसंपत्ति	नियोजित पूंजी की राशि
एकाधिकार सीपीएसई				
2017-18	59	10,96,052	16,50,650	9,74,232
2018-19	60	13,16,894	19,31,391	12,62,577
2019-20	63	12,50,715	20,63,078	14,07,094
गैर-एकाधिकार सीपीएसई				
2017-18	340	8,31,249	29,48,889	17,97,099
2018-19	347	8,61,280	32,77,405	20,59,972
2019-20	364	9,63,362	36,19,987	23,30,156
कुल				
2017-18	**399**	**19,27,301**	**45,99,539**	**27,71,331**
2018-19	**407**	**21,78,174**	**52,08,796**	**33,22,549**
2019-20	**427**	**22,14,077**	**56,83,065**	**37,37,250**

सरकारी कंपनियों तथा निगमों के संबंध में उत्पादन का मूल्य 2018-19 में ₹ 21,78,174 करोड़ से 2019-20 के दौरान ₹ 35,903 करोड़ (1.65 प्रतिशत) तक मामूली रूप से बढ़कर 2019-20 में ₹ 22,14,077 करोड़ हुआ, जबकि इसी अवधि में कुल परिसंपत्तियां और नियोजित पूंजी बढ़कर क्रमश: ₹ 4,74,269 करोड़ (9.11 प्रतिशत) तथा ₹ 4,14,701 करोड़ (12.48 प्रतिशत) हो गई।

1.4.2 नियोजित पूंजी पर प्रतिफल (आरओसीई)

आरओसीई एक ऐसा अनुपात है जो कंपनी की लाभ प्रदता और दक्षता को मापता है जिसके साथ इसकी पूंजी नियोजित होती है। आरओसीई की संगणना को ब्याज और करों

(ईबीआईटी) से पहले कंपनी की आय को नियोजित[33] पूंजी के द्वारा विभाजित करके किया जाता है। आरओसीई का सीपीएसई वार विवरण *परिशिष्ट-IX* में दिया गया हैं। 2017-18 से 2019-20 की अवधि के दौरान 425 सरकारी कम्पनियों और निगमों[34] के समेकित आरओसीई का ब्यौरा तालिका 1.16 में दिया गया हैं।

तालिका 1.16: नियोजित पूंजी पर प्रतिफल

वर्ष	ईबीआईटी (₹ करोड़ में)	नियोजित पूंजी (₹ करोड़ में)	आरओसीई (प्रतिशत में)
2017-18	2,91,064	24,69,196	11.79
2018-19	3,07,096	29,33,856	10.47
2019-20	2,10,823	33,04,146	6.38

2017-18 से 2019-20 तक विगत तीन वर्षों के दौरान सरकारी कम्पनियों तथा निगमों की आरओसीई में लगातार कमी पाई गई थी। ईबीआईटी में कमी तथा नियोजित पूंजी में वृद्धि के कारण वर्ष 2019-20 में आरओसीई सीमांत रूप से वर्ष 2018-19 की तुलना में काफी कम था।

एकाधिकार तथा गैर-एकाधिकार सीपीएसई के संबंध में आरओसीई नीचे तालिका 1.17 में दी गई है।

तालिका 1.17: एकाधिकार बनाम गैर एकाधिकार सीपीएसई के आरओसीई

वर्ष	एकाधिकार				गैर-एकाधिकार			
	सीपीएसई की संख्या	ईबीआईटी	नियोजित पूंजी	आरओसीई (%में)	सीपीएसई की संख्या	ईबीआईटी	नियोजित पूंजी	आरओसीई (%में)
		(₹ करोड़ में)				(₹ करोड़ में)		
2017-18	57	1,16,170	6,72,097	17.28	340	1,74,894	17,97,099	9.73
2018-19	58	1,14,218	8,73,884	13.07	347	1,92,878	20,59,972	9.36
2019-20	61	67,689	9,73,990	6.95	364	1,43,134	23,30,156	6.14

[33] नियोजित पूंजी = प्रदत्त शेयर पूंजी + मुक्त आरक्षित निधि और अधिशेष + दीर्घकालिक ऋण - संचित हानियां - आस्थगित राजस्व व्यय।

[34] भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण को छोड़कर जिन्हें शून्य लाभ/हानि सीपीएसई माना गया है क्योंकि उनकी हानि को फुटनोट 5 में दिए गए रूप में समायोजित किया गया है।

यह पाया गया था कि 2017-18 से 2019-20 तक विगत तीन वर्षों के दौरान एकाधिकार सरकारी कम्पनियों तथा निगमों की आरओसीई गैर-एकाधिकार सरकारी कम्पनियों तथा निगमों से अधिक था। वर्ष 2019-20 में एकाधिकार सरकारी कम्पनियों तथा निगमों की आरओसीई वर्ष 2018-19 की तुलना में मुख्य रूप से कम हुई जो मुख्यतया ईबीआईटी में कमी तथा नियोजित पूंजी में वृद्धि के कारण थी।

1.4.3 सीपीएसई की इक्विटी पर रिटर्न (आरओई)

आरओई[35] शेयरधारकों की इक्विटी द्वारा निवल आय को विभाजित करके गणना की गई कंपनियों के वित्तीय प्रदर्शन का एक उपाय है। आरओई का सीपीएसई वार विवरण परिशिष्ट-X में दिया गया है। 2017-18 से 2019-20 की अवधि के दौरान 425 सरकारी कम्पनियों और निगमों का समेकित आरओई तालिका 1.18 में दिया गया है।

तालिका 1.18: इक्विटी पर प्रतिफल

वर्ष	कर और वरीयता लाभांश के बाद निवल लाभ (₹ करोड़ में)	इक्विटी (₹ करोड़ में)	आरओई (प्रतिशत में)
2017-18	1,24,449	9,02,640	13.79
2018-19	1,35,660	9,63,594	14.08
2019-20	72,182	9,58,191	7.53

यह देखा गया कि वर्ष 2017-18 की तुलना में वर्ष 2018-19 में 425 सरकारी कम्पनियों तथा निगमों[36] का आरओई थोड़ा अधिक था। हालांकि, वर्ष 2018-19 की तुलना में वर्ष 2019-20 में सरकारी कम्पनियों तथा निगमों की आरओई में कमी मुख्यत: निवल लाभ में कमी के कारण थी।

एकाधिकार तथा गैर-एकाधिकार सीपीएसई के संबंध में आरओई तालिका 1.19 में दी गई है।

---

*[35] इक्विटी पर प्रतिफल = (कर और वरीयता लाभांश/इक्विटी के बाद निवल लाभ) *100 जहां इक्विटी = प्रदत्त पूंजी + निर्बाध आरक्षित निधियां - संचित हानियां - आस्थिगत राजस्व व्यय*

[36] भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण को छोड़कर जिन्हें शून्य लाभ/हानि सीपीएसई माना गया है क्योंकि उनकी हानि को फुटनोट 5 में दिए गए रूप में समायोजित किया गया है।

तालिका 1.19: एकाधिकार बनाम गैर-एकाधिकार सीपीएसई की आरओई

वर्ष	एकाधिकार				गैर-एकाधिकार			
	सीपीएसई की संख्या	इक्विटी (₹ करोड़ में)	कर तथा वरीयता लाभांश के बाद निवल लाभ (₹ करोड़ में)	आरओई (प्रतिशत में)	सीपीएसई की संख्या	इक्विटी (₹ करोड़ में)	कर तथा वरीयता लाभांश के बाद निवल लाभ (₹ करोड़ में)	आरओई (प्रतिशत में)
2017-18	57	4,41,820	67,349	15.24	340	4,60,820	57,101	12.39
2018-19	58	4,77,224	68,567	14.37	347	4,86,370	67,093	13.79
2019-20	61	5,07,535	32,779	6.46	364	4,50,656	39,403	8.74

यह पाया गया कि एकाधिकार सरकारी कम्पनियों तथा निगमों का आरओई 2017-18 तथा 2018-19 वर्षों के दौरान गैर-एकाधिकार सरकारी कम्पनियों तथा निगमों से उच्च था, जबकि यह 2019-20 में कम था। एकाधिकार सरकारी कम्पनियों तथा निगमों का आरओई वर्ष 2018-19 की तुलना में वर्ष 2019-20 में उल्लेखनीय रूप से कम था जो निवल लाभ में कमी तथा इक्विटी में वृद्धि के कारण था।

सरकारी कम्पनियों तथा निगमों का क्षेत्र वार आरओई, जहां क्षेत्र की कुल इक्विटी वर्ष 2019-20 के दौरान ₹ 10,000 करोड़ से अधिक है, को तालिका 1.20 में दर्शाया गया है।

तालिका 1.20: ₹ 10,000 करोड़ और अधिक की कुल इक्विटी के साथ क्षेत्रों का आरओई

(प्रतिशत में)

क्र.सं.	क्षेत्र	2019-20 के दौरान आरओई	2018-19 के दौरान आरओई	2017-18 के दौरान आरओई
1	पेट्रोलियम	3.40	15.99	16.77
2	बिजली	12.88	13.22	12.95
3	परिवहन सेवाएं	-17.65	-18.04	-5.69
4	वित्तीय सेवाएं	18.33	24.46	25.96

5	कोयला और लिग्नाइट	65.40	72.46	43.02
6	खनिज और धातु	10.22	17.95	15.33
7	बीमा	-17.19	-3.34	8.61
8	भारी उद्योग	-5.85	3.77	3.68
9	इस्पात	-15.27	16.04	-11.73
10	परिवहन उपकरण	22.89	24.87	17.12

1.4.4 सरकारी निवेशों पर वास्तविक प्रतिफल की दर (आरओआरआर)

आरओआरआर उस लाभप्रदता और दक्षता को मापती है जिसके साथ इक्विटी और, इसी तरह की गैर-ब्याज वहन करने वाली पूंजी को नियोजित किया गया है, जिसकी उनके समय के मूल्य के लिए उन्हें समायोजित करने और महत्व को मानने के बाद जब पारंपरिक प्रतिफल की दर (आरओआर) की तुलना में पीएटी को विभाजित करके गणना की जाती है, तो इस तरह के सभी निवेशों का योग ऐतिहासिक लागत के आधार पर गिना जाता है।

इस प्रतिवेदन में शामिल 607 सीपीएसई में से 193 सरकारी कम्पनियों में केन्द्र सरकार का प्रत्यक्ष निवेश हैं। इन 193 सीपीएसई में से लेखापरीक्षा ने 136 सीपीएसई (54 सूचीबद्ध सीपीएसई तथा 82 गैर सूचीबद्ध सीपीएसई) के संबंध में आरओआरआर की जांच की।

इन सीपीएसई में केन्द्रीय सरकार के निवेश के आरओआरआर की निम्नलिखित मान्यताओं के आधार पर संगणना की गई थी:

- इक्विटी के रूप में सीपीएसई में केंद्र सरकार द्वारा वास्तविक आधान के अलावा, केंद्र सरकार द्वारा सीपीएसई को दिए गए परिचालन और प्रशासनिक व्ययों के लिए ब्याज मुक्त ऋण और अनुदान/सब्सिडी, केंद्र सरकार द्वारा निवेश आधान के रूप में माना जाता है।
- उन मामलों में जहां सीपीएसई को दिए गए ब्याज मुक्त ऋण बाद में इक्विटी में बदल दिए गए थे, इक्विटी में परिवर्तित ऋण की राशि ब्याज मुक्त ऋण की राशि से कम कर ली गई है और उस वर्ष की इक्विटी में जोड़ दी गई है।
- वर्ष के अंत में कुल निवेश की गणना करते समय विनिवेश में कटौती की गई है।

- **संबंधित वित्तीय वर्ष[37] के लिए केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों पर भारित औसत ब्याज दर को वर्तमान मूल्य (पीवी) पर पहुंचने के लिए मिश्रित दर के रूप में अपनाया गया था क्योंकि वे वर्ष के लिए निधियों के निवेश के प्रति सरकार द्वारा व्यय की लागत का द्योतक हैं और इसलिए सरकार द्वारा किए गए निवेश पर प्रतिफल की न्यूनतम प्रत्याशित दर के रूप में माना गया है।**
- **केन्द्र सरकार के निवेश के आरओआरआर की गणना के उद्देश्य हेतु 2000-01 से शुरू होकर 2019-20 तक की अवधि को, लिया गया है जो 31 मार्च 2000 तक इन 136 सीपीएसई में केन्द्र सरकार के निवेश को 2000-01 की शुरूआत में केन्द्र सरकार के निवेश के वर्तमान मूल्य के रूप में मानते हुए लिया हैं।**
- **193 सीपीएसई में से 136 सीपीएसई के संबंध में आरओआरआर की गणना की गई थी जबकि 57 सीपीएसई से संबंधित डेटा उपलब्ध नहीं कराए जा सके।**

तालिका 1.21: केन्द्र सरकार द्वारा निवेश की वर्ष-वार विवरण तथा 2000-01 से 2019-20 तक सरकारी निधि का आरओआरआर

(₹ लख में)

वित्तीय वर्ष	वर्ष की शुरूआत में केन्द्र सरकार के कुल निवेश का वर्तमान मूल्य	वर्ष के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा डाली गई इक्विटी	वर्ष के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा अनुदित ब्याज मुक्त ऋण	वर्ष के दौरान ब्याज मुक्त ऋण का इक्विटी में परिवर्तन	केन्द्र सरकार द्वारा परिचालनऔर प्रशासनिक व्यय हेतु दी गई सहायता अनुदान	अंकित मूल्य पर वर्ष के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा विनिवेश	वर्ष के दौरान कुल निवेश	वर्ष के अंत में कुल निवेश	ब्याज की औसत दर	वर्ष के अंत में कुल निवेश का वर्तमान मूल्य	वर्ष के लिए धन की लागत की वसूली के लिए न्यूनतम अपेक्षित रिटर्न	वर्ष की कुल आय	आरओआरआर (प्रतिशत में)
ए	बी	सी	डी	ई	एफ	जी	एच= सी+डी-ई+एफ-जी	आई = बी+एच	जे	के = आई*(1+जे/100)	एल = I*जे/100	एम	एन = एम*100/के
2000-01	5364546.58	1489556.27	63400.00	4053.41	7979.18	12971.39	1543910.7	6908457.23	10.95	7664933.30	756476.07	1754319.79	22.89
2001-02	7664933.30	254920.77	40220.00	0.00	5497.17	0.00	300637.94	7965571.24	9.44	8717521.17	751949.93	2474736.40	28.39
2002-03	8717521.17	184944.74	14232.00	0.00	12745.35	30702.00	181220.09	8898741.26	7.34	9551908.86	653167.61	3134504.81	32.82
2003-04	9551908.86	396703.19	17002.00	0.00	5794.73	113823.88	305676.04	9857584.90	5.71	10420453.00	562868.10	4596203.80	44.11

[37] *सरकारी प्रतिभूतियों पर भारित औसत ब्याज की दर को भारतीय रिजर्व बैंक की सरकारी प्रतिभूति बाजार रिपोर्ट/सरकारी ऋण पर वित्त मंत्रालय के प्रास्थिति दस्तावेज से लिया गया है।*

2004-05	10420453.00	257239.87	5257.41	0.00	60181.50	43291.50	279387.28	10699840.28	6.11	11353600.52	653760.24	5921422.53	52.15
2005-06	11353600.52	240771.33	14340.00	0.00	15357.00	0.00	270468.33	11624068.85	7.34	12477275.50	853206.65	5947656.62	47.67
2006-07	12477275.50	1131714.66	1260.00	0.00	11264.37	0.00	1144239	13621514.53	7.89	14696252.03	1074737.50	7755037.65	52.77
2007-08	14696252.03	541041.15	3003.00	103320.00	46586.96	21605.36	465705.75	15161957.79	8.12	16393108.76	1231150.97	7492522.13	45.71
2008-09	16393108.76	303093.66	4744.00	0.00	13504.66	-23530.01	344872.33	16737981.09	7.69	18025131.83	1287150.75	8044154.81	44.63
2009-10	18025131.83	492352.83	9544.00	0.00	282510.42	104648.87	679758.37	18704890.21	7.23	20057253.77	1352363.56	7789767.80	38.84
2010-11	20057253.77	386934.55	53401.00	0.00	63809.00	156826.44	347318.11	20404571.88	7.92	22020613.97	1616042.09	7903567.37	35.89
2011-12	22020613.97	466996.54	34588.00	8521.12	804.84	26759.64	467108.62	22487722.59	8.52	24403676.55	1915953.96	8215620.57	33.67
2012-13	24403676.55	613941.07	34309.00	0.00	16254.35	138186.71	526317.72	24929994.27	8.36	27014141.79	2084147.52	10254405.08	37.96
2013-14	27014141.79	467331.91	41445.00	0.00	45788.49	190978.68	363586.72	27377728.51	8.45	29691146.57	2313418.06	11106790.13	37.41
2014-15	29691146.57	316386.45	37670.00	0.00	24575.27	84328.65	294303.07	29985449.64	8.51	32537211.40	2551761.76	9173665.54	28.19
2015-16	32537211.40	611725.59	47271.00	23101.14	67276.89	150870.99	552301.35	33089512.76	7.89	35700275.31	2610762.56	9974233.20	27.94
2016-17	35700275.31	987201.29	84785.00	10177.52	77374.16	294662.44	844520.49	36544795.80	7.16	39161403.18	2616607.38	9655471.95	24.66
2017-18	39161403.18	1048132.62	117658.00	0.00	102538.18	166117.90	1102210.9	40263614.08	6.97	43069987.98	2806373.90	10915455.21	25.34
2018-19	43069987.98	1179466.25	112440.00	0.00	373538.86	416793.06	1248652	44318640.02	7.78	47766630.22	3447990.19	10867778.87	22.75
2019-20	47766630.22	2049857.83	30952.00	0.00	1036467.90	640444.77	2476833	50243463.18	6.85	53685140.41	3441677.23	6270654.20	11.68
							13739028	449826100.1					

आरओआरआर ने 2004-05 तक एक बढ़ती प्रवृत्ति को दिखाया और 2006-07 में यह 52.77 प्रतिशत तक पहुंच गया जिसके बाद इसमें गिरावट शुरू हो गई और 2015-16 से 2019-20 तक पिछले पांच वर्षों के दौरान 27.94 प्रतिशत और 11.68 प्रतिशत के बीच रही।

तालिका 1.22: वर्ष 2019-20 के लिए केन्द्र सरकार के निवेश पर समेकित आरओआरआर की दर

	केंद्र सरकार द्वारा 2019-20 तक निवेश (₹ लाख में)	ऐतिहासिक मूल्य के आधार पर केंद्र सरकार के निवेश पर रिटर्न (प्रतिशत में)	2019-20 के अंत में केंद्र सरकार के निवेश का वर्तमान मूल्य (₹ लाख में)	निवेश के वर्तमान मूल्य (प्रतिशत में) पर विचार करते हुए केंद्र सरकार के निवेश पर आरओआरआर
क	**ख**	**ग**	**घ**	**ड**
उपरोक्त तालिका के स्तम्भ का मूल्य	**उपरोक्त स्तम्भ का कुल + 2000-01 के शुरू में सरकारी निवेश**	**क** *100/ **ख**	**उपरोक्त तालिका के स्तम्भ का मूल्य**	**ए***100/ **घHHHHH**
62,70,654	1,91,03,575 (1,37,39,028+53,64,547)	32.82	5,36,85,140	11.68

पिछले तीन वर्षों का कंपनी वार आरओआरआर *परिशिष्ट XI* में दिया गया हैं।

उसी के अवलोकन से प्रकट होता है कि सूचीबद्ध कंपनियों ने पूर्ववर्ती तीन वर्षों के दौरान 53.43 प्रतिशत और 33.59 प्रतिशत के बीच आरओआरआर दिया है, जब कि असूचीबद्ध सीपीएसई ने तीन पूर्ववर्ती वर्षों 2017-18 से 2019-20 के दौरान -2.52 प्रतिशत तथा -7.46 प्रतिशत के बीच नकारात्मक रिटर्न दिया है।

केन्द्र सरकार के निवेश आरओआरआर की तुलना एकाधिकार तथा गैर एकाधिकार कम्पनियों के तहत 136 सूचीबद्ध तथा असूचीबद्ध सीपीएसई के लिए निवेश के एतिहासिक मूल्य के आधार पर रिटर्न से की गई थी। वर्ष 2019-20 के परिणाम तालिका 1.23 में दिए गए है:

तालिका 1.23: वर्ष 2019-20 के लिए एकाधिकार और गैर-एकाधिकार सीपीएसई के लिए केंद्र सरकार के निवेश पर आरओआरआर

	2019-20 में कुल आय/हानि (₹ लाख में)	2019-20 तक केंद्र सरकार द्वारा निवेश शुरू होने से (₹ लाख में)	ऐतिहासिक मूल्य के आधार पर केंद्र सरकार के निवेश पर रिटर्न (प्रतिशत में)	2019-20 के अंत में केंद्र सरकार के निवेश का वर्तमान मूल्य (₹ लाख में)	निवेश के वर्तमान मूल्य (प्रतिशत में) पर विचार करते हुए केंद्र सरकार के निवेश पर आरओआरआर
सूचीबद्ध एकाधिकार सीपीएसई	27,66,290	12,19,366	226.86	28,36,956	97.51
सूचीबद्ध गैर-एकाधिकार सीपीएसई	56,41,107	54,88,798	102.77	2,21,91,506	25.42
समेकित सूचीबद्ध	84,07,397	67,08,164	125.33	2,50,28,462	33.59
असूचीबद्ध एकाधिकार सीपीएसई	(-)94,350	50,46,063	(-)1.87	83,67,860	(-)1.13
असूचीबद्ध-एकाधिकार सीपीएसई	(-)20,42,394	73,49,347	(-)27.79	2,02,88,818	(-)10.07

समेकित असूचीबद्ध	(-)21,36,743	1,23,95,410	(-)17.24	2,86,56,678	(-)7.46

यह पाया गया था कि सूचीबद्ध सीपीएसई का आरओआरआर असूचीबद्ध सीपीएसई से उच्च था। कुल मिलाकर एकाधिकार सीपीएसई का आरओआरआर गैर-एकाधिकार सीपीएसई की तुलना में उच्चतर था। 54 सूचीबद्ध सीपीएसई के आरओआरआर के साथ एतिहासिक मूल्य पर आधारित केन्द्र सरकार के निवेश पर रिटर्न की सीपीएसई वार तुलना *परिशिष्ट-XII* में दी गई है। यह पाया गया था कि 54 सूचीबद्ध सीपीएसई में से 52 सीपीएसई के संबंध में एतिहासिक मूल्य के आधार पर केन्द्र सरकार के निवेश पर रिटर्न की तुलना में आरओआरआर कम था। अन्य दो सीपीएसई, जहां एतिहासिक मूल्य के आधार केन्द्र सरकार के निवेश पर रिटर्न की तुलना में आरओआरआर उच्च था, एमओआईएल लिमिटेड तथा भारत इलैक्ट्रोनिक्स लिमिटेड थी क्योंकि विनिवेश प्राप्ति राशि केन्द्र सरकार द्वारा किए गए निवेश के एतिहासिक मूल्य से उच्च थी।

1.4.5 सूचीबद्ध सीपीएसई के निवेश पर रिटर्न (आरओआई)

54 सीपीएसई में केंद्र सरकार द्वारा किए गए निवेश से प्राप्त लाभ का निर्धारण करने के लिए स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध इन सीपीएसई के निवेश पर रिटर्न (वार्षिक औसत दर)[38] की गणना 2000-2001 से की गई है। आरओआई एक निष्पादन माप है जिसका उपयोग किसी निवेश की दक्षता का मूल्यांकन करने के लिए किया जाता है। इन सीपीएसई के

[38] *{(वित्तीय वर्ष के 31 मार्च को कंपनी के बाजार पूंजीकरण का सरकारी हिस्सा + वित्त वर्ष के 31 मार्च को सरकार के लाभांश प्राप्तियों का वर्तमान मूल्य + वित्त वर्ष के 31 मार्च के अनुसार सरकार के विनिवेश प्राप्तियों का वर्तमान मूल्य) - (स्थापना पर सरकार की प्रदत्त इक्विटी + स्थापना पर सरकार के द्वारा इनफ्यूज्ड इक्विटी का रियायती मूल्य + स्थापना पर परिचालन तथा प्रशासनिक व्ययों की पूर्ति के लिए इनफ्यूज्ड आर्थिक सहायता/अनुदान का रियायती मूल्य)/(स्थापना पर सरकारकी प्रदत्त इक्विटी + स्थापना पर सरकार के द्वारा इनफ्यूज्ड इक्विटी का रियायती मूल्य + स्थापना पर परिचालन तथा प्रशासनिक व्ययों की पूर्ति के लिए इनफ्यूज्ड आर्थिक सहायता/अनुदान का रियायतीमूल्य)100/बीच की वार्षिक अवधि की संख्या।*

आरओआई (वार्षिक औसत दर) की निम्नलिखित मान्यताओं के आधार पर संगणना की गई थी:

- **इक्विटी के रूप में सीपीएसई में केंद्र सरकार द्वारा वास्तविक आधान के अलावा, केंद्र सरकार द्वारा सीपीएसई को दिए गए परिचालन और प्रशासनिक व्ययों के लिए अनुदान/सब्सिडी, शुरुआत में उनके मूल्यों की पुन: गणना द्वारा केंद्र सरकार द्वारा निवेश आधान अथवा आउटफ्लो के रूप में माना जाता है।**
- **वर्ष के अंत में सीपीएसई के बाजार पूंजीकरण और लाभांश प्राप्तियों और विनिवेश प्राप्तियों के वर्तमान मूल्य को स्थापना के बाद से इनफ्लो माना गया है।**
- **वित्त वर्ष 2000-01 को स्थापना वर्ष के रूप में माना गया हैं। सीपीएसई के लिए उपलब्ध डेटा 2000-01 को स्थापना वर्ष के रूप में मानने का कारण है।**

आरओआई (वार्षिक औसत दर) के अलावा, इन सीपीएसई की सीपीएसई वार चक्र वृद्धि वार्षिक वृद्धि दर[39] (सीएजीआर) की निवेश की रिटर्न की दर निर्धारित करने के लिए भी गणना की गई है।

सीपीएसई में केंद्र सरकार के ऐसे निवेश के आरओआई तथा सीएजीआर (वार्षिक औसत दर) की समेकित स्थिति को तालिका 1.24 में दर्शाया गया है।

[39]चक्र वृद्धि वार्षिक वृद्धिदर ज्यामितीय प्रगति अनुपात को इंगित करता है जो समय अवधि पर निरंतर दर प्रदान करता है।

तालिका 1.24: वर्ष 2000-01 से 2019-20 के दौरान केंद्र सरकार द्वारा अन्र्वाह और केंद्र सरकार द्वारा बहिर्वाह और आरओआई तथा सीएजीआर का वर्षवार विवरण

(₹ लाख में)

वर्ष	केंद्र सरकार द्वारा आयोजित इक्विटी	केंद्र सरकार द्वारा जोड़ी गई इक्विटी	केंद्र सरकार द्वारा दी जाने वाली सब्सिडी	केंद्र सरकार द्वारा लाभांश प्राप्तियां	केंद्र सरकार द्वारा विनिवेश प्राप्तियां	वर्षों की संख्या	ब्याज दर (आर)	झ+ब	इक्विटी का स्थापना मूल्य जोड़ा गया	अनुदान का स्थापना मूल्य \ सब्सिडी	विनिवेश प्राप्तियों का पीवी	लाभांश प्राप्तियों का पीवी	निवेश की लागत	शेयर का बाजार मूल्य	निवेश का वर्तमान मूल्य	आरओआई (वार्षिक औसत दर)	आरओआई (सीएजीआर)
क	ख	ग	घ	ड	च	छ	ज	झ	ञ	त	थ	द	ध	न	प	फ	ब
								(1+ज)	सी/मैं के उत्पाद की स्थापना के वर्ष मूल्य के लिए (छ -1)	घ /उत्पाद की स्थापना के बाद से वर्ष मूल्य (छ -1)	वर्ष से पिछले वर्ष तक मैं के च * उत्पाद	वर्ष से पिछले वर्ष तक आई का ई * उत्पाद	ख +Σ ञ +Σ त		न +Σ थ +Σ द	((ब - ध)/ ध)/ छ *100	((प / ध)^1/ छ - 1)*100
2000-01	1123309	41010	0	260949	12792	1	0.1095	1.1095	41010	0	53830	1098066	1164319	3698737	4850633	316.61	316.61
2001-02	1111402	8615	0	353168	0	2	0.0944	1.0944	7765	0	0	1339450	1160177	5141421	7632766	278.95	156.50
2002-03	1120424	4981	0	648409	0	3	0.0734	1.0734	4102	0	0	2247074	1173301	5515692	10254111	257.98	105.98
2003-04	1120424	38649	384	683554	1216976	4	0.0571	1.0571	29653	295	3929063	2206885	1203249	14046223	24920591	492.78	113.33
2004-05	1901679	22550	59110	1154740	268407	5	0.0611	1.0611	16367	42902	819757	3526754	2043773	23016293	38237172	354.18	79.64
2005-06	1901679	13578	2000	1134864	0	6	0.0734	1.0734	9287	1368	0	3266469	2054428	36851808	55339156	432.28	73.14
2006-07	2004724	151848	9277	1334669	0	7	0.0789	1.0789	96763	5912	0	3578876	2260148	38702557	60768781	369.82	60.04
2007-08	2387346	26085	39652	1429807	99482	8	0.0812	1.0812	15406	23420	247250	3553606	2681596	78860843	104727922	475.68	58.11

2008-09	2387346	68391	13180	1340456	0	9	0.0769	1.0769	37360	7200	0	3081330	2726157	57815312	86763722	342.52	46.88
2009-10	3526595	125038	282000	1571232	2267040	10	0.0723	1.0723	63428	143050	4839156	3353905	4071883	100640308	137781778	328.37	42.21
2010-11	4480096	225217	18000	2065446	2214954	11	0.0792	1.0792	106543	8515	4409191	4111573	5140442	117267448	162929682	279.05	36.92
2011-12	4480096	8671	0	2540757	1389405	12	0.0852	1.0852	3801	0	2562837	4686572	5144243	88476618	141388261	220.71	31.80
2012-13	4592296	49199	13000	2785930	2404814	13	0.0836	1.0836	19873	5251	4087558	4735356	5281568	71191349	132925906	185.91	28.16
2013-14	4592296	73364	0	3752151	1423613	14	0.0845	1.0845	27348	0	2233086	5885639	5308916	66214638	136067920	175.93	26.07
2014-15	4595911	19200	16500	2855537	2432259	15	0.0851	1.0851	6600	5671	3517982	4130206	5324802	80797181	158298652	191.52	25.38
2015-16	4595911	12003	55202	3369753	1850317	16	0.0789	1.0789	3802	17486	2466381	4491714	5346090	64959270	149418836	168.43	23.14
2016-17	4595911	477947	60881	3649950	2952040	17	0.0716	1.0716	140327	17875	3647163	4509410	5504291	87475931	180092070	186.58	22.77
2017-18	4967158	431016	55437	3736271	4344269	18	0.0697	1.0697	118092	15189	5008606	4307631	6008819	96830604	198762980	178.21	21.46
2018-19	5002984	71324	368453	3421956	4031110	19	0.0778	1.0778	18269	94373	4344730	3688184	6157288	78761971	188727261	156.06	19.74
2019-20	5223730	175698	697555	2987694	1243307	20	0.0685	1.0685	41754	165770	1431829	3440716	6585557	49331450	164169285	119.64	17.45

आरओआई (वार्षिक औसत दर) 2007-08 के बाद से निरंतर गिरावट दर्शाता है चूकिं 2007-08 में आरओआई 475.68 प्रतिशत था तथा, जो 2019-20 में घटकर 119.64 प्रतिशत हो गया है।

एकाधिकार और गैर-एकाधिकार कंपनियों की श्रेणी के तहत सूचीबद्ध सीपीएसई आरओआई (वार्षिक औसत दर) और आरओआई (सीएजीआर) की गणना को किया गया था और पिछले तीन वर्षों के परिणाम तालिका 1.25 में दिए गए हैं:

तालिका 1.25: 2017-18 से 2019-20 के दौरान एकाधिकार और गैर-एकाधिकार सूचीबद्ध सीपीएसई के लिए आरओआई (औसत वार्षिक दर) और आरओआई (सीएजीआर)

(प्रतिशत में)

	आरओआई (औसत वार्षिक दर)			आरओआई (सीएजीआर)		
	2017-18	2018-19	2019-20	2017-18	2018-19	2019-20
सूचीबद्ध एकाधिकार सीपीएसई	544.37	504.81	404.64	29.08	27.22	24.64
सूचीबद्ध गैर-एकाधिकार सीपीएसई	137.37	117.58	88.04	19.77	18.03	15.74

पिछले तीन वर्षों के लिए सूचीबद्ध सीपीएसई वार आरओआई (औसत वार्षिक दर) और आरओआई (सीएजीआर) तालिका 1.26 में दिया गया है:

तालिका 1.26: 2017-18 से 2019-20 के दौरान सीपीएसई के आरओआई (औसत वार्षिक दर) और आरओआई (सीएजीआर)

क्र.सं.	सीपीएसई	आरओआई (औसत वार्षिक दर)			आरओआई (सीएजीआर)		
		2017-18	2018-19	2019-20	2017-18	2018-19	2019-20
1.	**भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स**	726.42	677.61	453.85	31.15	29.19	25.35

	लिमिटेड						
2.	**इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड**	603.63	522.44	428.42	29.82	27.45	25
3.	**पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड**	187.35	196.58	162.91	30.08	28.69	25.41
4.	**गेल (इंडिया) लिमिटेड**	430.84	421.7	206.89	27.43	26.03	20.6
5.	**आवास और शहरी विकास निगम लिमिटेड**	501.95	159.15	50.43	501.95	104.52	35.95
6.	**आईएफसीआई लिमिटेड**	28.39	15.7	1.47	18.03	11.17	1.4
7.	**इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड**	411.3	386.65	292.48	27.11	25.47	22.67
8.	**एमओआईएल लिमिटेड**	628.8	523.35	423.92	63.59	53.78	45.79
9.	**नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड**	56.91	47.29	38.4	14.39	12.87	11.41
10.	**एनएचपीसी लिमिटेड**	35.63	30.97	26.03	17.31	15.14	13.07
11.	**एनटीपीसी लिमिटेड**	203.61	188.55	152.5	27.35	25.25	22.41
12.	**पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड**	179.4	119.75	92.68	31.73	25.57	21.85

13.	**स्कूटर इंडिया लिमिटेड**	31.42	18.09	10.1	11.1	8.16	5.68
14.	**एसजेवीएन लिमिटेड**	51.67	39.51	34.86	22.69	18.35	16.2
15.	**एनएमडीसी लिमिटेड**	2160.74	2011.28	1822.96	39.3	36.76	34.32
16.	**भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड**	1807.48	1339.2	1159.27	37.93	33.88	31.33
17.	**भारत डायनेमिक्स लिमिटेड**	3679.36	1449.87	743.7	3679.36	447.7	185.66
18.	**बीईएमएल लिमिटेड**	725.69	675.53	364.76	31.14	29.17	24.01
19.	**बामर लॉरी इन्वेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड**	387.52	382.84	329.69	29.56	27.96	25.58
20.	**कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड**	1646.53	1642.45	1152.43	37.22	35.32	31.29
21.	**एचएमटी लिमिटेड**	14.37	13.01	7.53	7.35	6.77	4.7
22.	**भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड**	764.33	702.81	606.43	31.52	29.43	27.17
23.	**तेल और प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड**	662.63	615.66	578.04	30.49	28.54	26.86

24.	**केआईओसीएल लिमिटेड**	2104.56	677.5	185.22	2104.56[40]	281.44	87.17
25.	**मिश्रधातु निगम लिमिटेड**	**लागू नहीं**[41]	1335.72	867.76	**लागू नहीं**	1335.72	328.43
26.	**न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड**	14449.39	4477.51	2090.2	14449.39	851.58	299.39
27.	**जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड**	15723.81	3203.67	873.53	15723.81	706.68	200.76
28.	**हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड**	11389.47	4047.95	2301.4	11389.47	805.31	312.21
29.	**महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड**	38.34	32.7	28.1	12.17	10.96	9.91
30.	**कोल इंडिया लिमिटेड**	638.84	543.59	433.43	63.91	54.42	46.11
31.	**ऑयल इंडिया लिमिटेड**	779.18	627.32	487.94	60.61	51.51	43.87
32.	**स्टील अथॉरिटी**	74.89	63.36	45.95	16.01	14.47	12.31

[40] *2017-18 के दौरान कंपनी के शेयर का बाजार मूल्य ₹219.15 था जो 2018-19 में ₹141.65 और 2019-20 में ₹59.40 तक कम हो गया। इसके अलावा, 2017-18 कंपनी की लिस्टिंग का पहला वर्ष था और तालिका 1.24 के अनुसार आरओआई (वार्षिक औसत दर) और आरओआई (सीएजीआर) गणना के लिए हर बाद के वर्ष की संख्या में भी वृद्धि हो जाती है। यह सब एक ही और उच्च आरओआई (वार्षिक औसत दर) और आरओआई (सीएजीआर) 2017-18 के दौरान की गणना की है जो बाद के वर्षों में कम हुई।*

[41] *एनए यह दर्शाता है कि सीपीएसई को उस वर्ष में सूचीबद्ध नहीं किया गया था बल्कि बाद के वर्ष में सूचीबद्ध किया गया था।*

	ऑफ इंडिया लिमिटेड						
33.	**एंड्रयू यूल एंड कंपनी लिमिटेड**	27.47	15.83	3.3	10.41	7.58	2.56
34.	**हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड**	108.69	90.48	61.47	18.29	16.5	13.81
35.	**एमएसटीसी लिमिटेड**	**लागू नहीं**	1149.25	460.48	**लागू नहीं**	1149.25	219.52
36.	**नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड**	183.11	170.51	146.42	21.63	20.28	18.59
37.	**शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड**	164.2	141.23	133.96	20.92	19.13	18.09
38.	**राष्ट्रीय रसायन और उर्वरक लिमिटेड**	60.38	51.31	6.11	14.73	13.31	4.07
39.	**हिंदुस्तान ऑर्गेनिक्स केमिकल्स लिमिटेड**	(-)3.16	(-)3	(-)4.07	(-)4.55	(-)4.35	(-)8.08
40.	**भारत इम्यूनोलॉजिकल एंड बायोलॉजिकल कॉर्पोरेशन लिमिटेड**	5.88	(-)1.03	(-)1.96	4.09	(-)1.14	(-)2.46
41.	**आईटीआई लिमिटेड**	8.6	7.69	3.24	5.33	4.85	2.53
42.	**एनएलसी (इंडिया)**	117.35	127.91	115.9	18.77	18.54	17.27

	लिमिटेड						
43.	**कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड**	5063.7	2139.79	1071.39	5063.7	561.78	221.21
44.	**उर्वरक और रसायन त्रावणकोर लिमिटेड**	37.75	19.53	15.05	12.09	8.5	7.19
45.	**मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड**	54.88	21.1	3.82	33.7	15.5	3.5
46.	**एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड**	1719.19	1005.26	303.27	116.91	83.99	49.73
47.	**एसटीसी लिमिटेड**	154.56	146.55	68.13	22.5	21.1	15.44
48.	**एमएमटीसी लिमिटेड**	857.41	667.12	393.94	36.08	32.16	26.81
49.	**भारतीय पर्यटन विकास निगम लिमिटेड**	723.83	389.85	163.9	88.2	61.2	39.22
50.	**गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड**	**लागू नहीं**	648.63	486.7	**लागू नहीं**	648.63	227.63
51.	**रेल विकास निगम लिमिटेड**	**लागू नहीं**	**लागू नहीं**	48.41	**लागू नहीं**	**लागू नहीं**	48.41
52.	**भारतीय रेलवे खानपान और पर्यटन निगम**	**लागू नहीं**	**लागू नहीं**	2265.10	**लागू नहीं**	**लागू नहीं**	2265.10
53.	**इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड**	**लागू नहीं**	4285.73	1942.62	**लागू नहीं**	4285.73	531.29

54.	**राइट्स लिमिटेड**	**लागू नहीं**	2517.34	1,336.20	**लागू नहीं**	2517.34	426.54

यह पाया गया कि सीपीएसई के आरओआई (वार्षिक औसत दर) तथा आरओआई (सीएजीआर) में बड़ा अन्तर है। बड़े अन्तरों के मुख्य कारण निम्न है:

- **सीपीएसई की वर्तमान सूचीबद्धता**
- **सीपीएसई के शेयर का बाजार मूल्य में उतार-चढ़ाव**
- **सीपीएसई में केन्द्र सरकार द्वारा प्राप्त लाभांश और विनिवेश में उतार-चढ़ाव**
- **सीपीएसई में केन्द्र सरकार द्वारा दी गई इक्विटी इन्फयूज़ड तथा अनुदान/सब्सिडी में उतार-चढ़ाव।**
- **वर्षों की संख्या जिनमें सीपीएसई में केन्द्र सरकार की निधि निवेश की गई।**

54 सूचीबद्ध सीपीएसई में से, 2017-18 में पांच सीपीएसई[42] सूचीबद्ध नहीं थी जबकि दो सीपीएसई[43] 2019-20 के दौरान सूचीबद्ध की गई थी। 54 सूचीबद्ध सीपीएसई के आरओआई (औसत वार्षिक दर) तथा आरओआई (सीएजीआर) की समीक्षा से यह पाया गया कि 2017-18 से 2019-20 तक विगत तीन वर्षों के दौरान 44 सीपीएसई के आरओआई (औसत वार्षिक दर) तथा 46 सीपीएसई के आरओआई (सीएजीआर) कम हुए हैं।

1.4.6 निजी कंपनियों के साथ सूचीबद्ध सीपीएसई का निष्पादन

पांच अनुपातों (आरओई, आरओसीई, प्रति शेयर आय, मूल्य आय अनुपात और आईसीआर) के मानकों पर 36[44] सूचीबद्ध सीपीएसई का निष्पादन 2015-16 से 2019-20 तक पिछले पांच वर्षों के दौरान समान प्रकृति वाले व्यवसाय की निजी कंपनियों के साथ तुलना की गई थी। तुलना में निम्नलिखित परिणाम सामने आए:

---

[42] *मिश्र धातू निगम लिमिटेड, एमएसटीसी लिमिटेड, गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड, इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड, राइट्स लिमिटेड।*

[43] *इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड और रेल विकास निगम लिमिटेड को 2019-20 के दौरान स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध किया गया था।*

[44] *पिछले पांच वर्षों के दौरान केवल 47 सीपीएसई के शेयरों का व्यापार किया गया। 11 सीपीएसई के मामले में समान प्रकृति वाली व्यवसाय की कोई सूचीबद्ध निजी कंपनियाँ नहीं मिलीं, इसलिए तुलना के लिए 36 सीपीएसई को माना गया।*

आरओआई: पिछले पांच वर्षों के दौरान तीन या अधिक वर्षों के लिए समान प्रकृति वाले व्यवसाय की निजी कंपनियों की तुलना में 36 सूचीबद्ध सीपीएसई में से 16 में आरओआई निचले स्तर पर था *(परिशिष्ट-XIII)*।

आरओसीई: पिछले पांच वर्षों के दौरान तीन या अधिक वर्षों के लिए समान प्रकृति वाले व्यवसाय की निजी कंपनियों की तुलना में 36 सूचीबद्ध सीपीएसई में से 17 में आरओसीई निचले स्तर था *(परिशिष्ट-XIV)*।

प्रति शेयर आय (ईपीएस): पिछले पांच वर्षों के दौरान तीन या अधिक वर्षों के लिए समान प्रकृति वाले व्यवसाय की निजी कंपनियों की तुलना में 36 सूचीबद्ध सीपीएसई में से 29 के सम्बन्ध में ईपीएस निचले स्तर पर था *(परिशिष्ट-XV)*।

मूल्य आय (पी/ई) अनुपात[45]: पिछले पांच वर्षों के दौरान तीन या अधिक वर्षों के लिए समान प्रकृति वाले व्यवसाय की निजी कंपनियों की तुलना में 36 सूचीबद्ध सीपीएसई में से 28 के सम्बन्ध में पी/ई अनुपात निचले स्तर पर था *(परिशिष्ट-XVI)*।

आईसीआर: पिछले पांच वर्षों के दौरान तीन या अधिक वर्षों के लिए समान प्रकृति वाले व्यवसाय की निजी कंपनियों की तुलना में 36 सूचीबद्ध सीपीएसई में से 17 के सम्बन्ध में आईसीआर निचले स्तर पर था (परिशिष्ट-XVII)।

दस सीपीएसई के संबंध में, तीन या अधिक वर्षों के दौरान एक ही क्षेत्र में निजी कंपनियों की तुलना में उपरोक्त सभी मानक कम थे। यह समान प्रकृति वाले व्यवसाय की निजी कम्पनियों की तुलना में उनके निम्न निष्पादन का सूचक है।

1.4.7 बिक्री और विपणन

2019-20 के दौरान 427 सरकारी कम्पनियों और निगमों की कुल बिक्री, 2018-19 के दौरान 407 सीपीएसई की कुल बिक्री ₹ 24,99,682 करोड़ की तुलना में, ₹ 24,33,337 करोड़ थी। इन 427 सीपीएसई, में से 130 सीपीएसई ने अपनी ₹ 11,58,179 करोड़ की बिक्री में से सरकारी क्षेत्र को ₹ 2,71,007 करोड़ की कीमत का माल बेचा/सेवाएं प्रदान की। सरकारी क्षेत्र को इन 130 सीपीएसई की बिक्री का कुल प्रतिशत उनकी कुल बिक्री के

---

[45] *मूल्य आय अनुपात (पी/ई अनुपात) वह अनुपात है जो कंपनी के मूल्यांकन के लिए है जो इसकी प्रति शेयर आय के सापेक्ष वर्तमान शेयर मूल्य को मापता हैं। पी/ईअनुपात की गणनाप्रति शेयर बाजार मूल्य/प्रति शेयर आयके रूप में की जाती हैं।*

संदर्भ में 23.42 प्रतिशत बनता था।

427 सीपीएसई में से 65 सीपीएसई ने ₹ 1,18,997 करोड़ (उनकी कुल बिक्री की राशि ₹ 18,56,711 करोड़ का 6.41 प्रतिशत) की कीमत का माल/सेवाएं निर्यात की जबकि 58 सीपीएसई ने ₹ 4,41,564 करोड़ की कीमत का माल/सेवाएं आयात की जिसके परिणामस्वरूप सीपीएसई द्वारा निवल आयात ₹ 3,22,567 करोड़ का था।

कुल बिक्री, सरकारी क्षेत्र को बिक्री तथा एकाधिकार तथा गैर-एकाधिकार सीपीएसई के संबंध में निर्यात का विवरण तालिका 1.27 में दिया गया है।

तालिका 1.27: एकाधिकार बनाम गैर-एकाधिकार सीपीएसई की बिक्री विवरण

(₹ करोड़ में)

टाइप/वर्ष	सीपीएसई का सं.	कुल बिक्री	सरकारी क्षेत्र को बिक्री	निर्यात बिक्री
एकाधिकार सीपीएसई				
2017-18	58	12,50,833	58,260	27,135
2018-19	60	14,95,642	46,501	42,995
2019-20	63	14,25,157	50,357	44,308
गैर-एकाधिकार सीपीएसई				
2017-18	332	9,03,889	1,76,977	48,191
2018-19	347	10,04,040	1,98,084	69,915
2019-20	364	10,08,180	2,20,650	74,689
कुल				
2017-18	**390**	**21,54,722**	**2,35,237**	**75,326**
2018-19	**407**	**24,99,682**	**2,44,585**	**1,12,910**
2019-20	**427**	**24,33,337**	**2,71,007**	**1,18,997**

427 सीपीएसई द्वारा, ₹ 24,33,337 करोड़ की कुल बिक्री के प्रति 65 सीपीएसई द्वारा निर्यात बिक्री 4.89 प्रतिशत थी (₹ 1,18,997 करोड़)। जिन सीपीएसई की निर्यात बिक्री ₹ 5,000 करोड़ से अधिक थी उन्हें तालिका 1.28 में दर्शाया गया था।

तालिका 1.28: 2019-20 के दौरान ₹ 5,000 करोड़ रुपये से अधिक की निर्यात बिक्री वाले सीपीएसई

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	सीपीएसई का नाम	निर्यात बिक्री
1	इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	21,841
2	मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड	20,823
3	ओएनजीसी विदेश लिमिटेड	12,192

4	भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड	9,167
5	ओएनजीसी पेट्रो एडिशंस लिमिटेड	8,220
6	तेल और प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड	6,289
7	हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड	6,203
कुल		**84,735**

इन सात सीपीएसई की निर्यात बिक्री सभी 65 सीपीएसई के कुल निर्यात का 71.21 प्रतिशत है।

1.4.8 अनुसंधान एवं विकास

प्रौद्योगिकी, उत्पाद या आविष्कार का पेटेंट किसी कंपनी के अधिकार को दूसरों को बनाने, उपयोग करने या बेचने से वर्जित करने में सक्षम बनाता है। यह विकास लागत को पुन प्राप्त करने और पेटेंट प्रौद्योगिकी के विकास में निवेश का रिटर्न प्राप्त करने में भी मदद करता है। पेटेंट का पंजीकरण जोखिम को सीमित करने में मदद करता है कि एक ही विचार पर विकसित प्रौद्योगिकी, उत्पाद या आविष्कार किसी अन्य कंपनी द्वारा प्राप्त किया जाएगा। तालिका 1.29 पिछले तीन वर्षों के दौरान पंजीकृत पेटेंट की तुलना में सीपीएसई वार आरएंडडी के व्यय को दर्शाती है:

तालिका 1.29 अनुसंधान एवं विकास के व्यय और पंजीकृत पेटेंट

2017-18		2018-19		2019-20	
आरएण्डआई व्यय (₹ करोड़ में)	पेटेंट पंजीकृत	आरएण्डआई व्यय (₹ करोड़ में)	पेटेंट पंजीकृत	आरएण्डआई व्यय (₹ करोड़ में)	पेटेंट पंजीकृत
5,320	339	5,435	371	4,816	1,061

यह पाया गया था कि आर एण्ड डी व्यय 2018-19 में ₹ 5,435 करोड़ से घटकर 2019-20 में ₹ 4,816 करोड़ होने से 2019-20 के दौरान ₹ 619 करोड़ कम हुआ जबकि उसी अवधि में पेटेंट पंजीकृत 690 से बढ़ गए।

2019-20 के दौरान 1061 पंजीकृत पेटेंट में से 58 पेटेंट का आठ सीपीएसई द्वारा वाणिज्यी करण कर दिया गया है और वर्ष 2019-20 के दौरान ₹ 275.47 करोड़ का राजस्व अर्जित हुआ जिसे नीचे दी गई तालिका 1.30 में वर्णित किया गया है।

तालिका 1.30: वाणिज्यीकृत पेटेंट की संख्या और अर्जित वाणिज्यिकरण

क्र.सं.	सीपीएसई का नाम	आरएण्डडी पर कुल व्यय (₹ करोड़ में)	पेटेंट पंजीकृत	पेटेंट का व्यावसायीकरण	पेटेंट के व्यावसायीकरण पर अर्जित राजस्व (₹ करोड़ में)
1	भारतीय कृत्रिम अंगविनिर्माण निगम लिमिटेड	0.53	1	1	0
2	भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड	92.18	12	4	254.07
3	इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	47.43	8	2	0
4	इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड	24.31	32	17	1.90
5	हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड	257.92	64	17	2.53
6	इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	428.04	123	14	0
7	कोनकन रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड	0	1	1	1.19
8	मिश्र धातु निगम लिमिटेड	7.96	3	2	15.78
	कुल	**858.37**	**244**	**58**	**275.47**

इसके अलावा 2019-20 के दौरान वे सीपीएसई जिनका आरएंडडी व्यय ₹ 500 करोड़ से अधिक हुआ था उन्हें तालिका 1.31 में दर्शाया गया है।

तालिका 1.31: ₹ 500 करोड़ से अधिक आरएंडडी व्यय वाली सीपीएसई

क्र.सं.	सीपीएसई का नाम	कुल आरएंडडी व्यय (₹ करोड़ में)	निवल लाभ (₹ करोड़ में)	आरएंडडी व्यय से निवल लाभ का प्रतिशत
1	हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड	1,232	2,832	43.50
2	भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड	947	1,794	52.79
3	तेल और प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड	556	13,445	4.14

यह पाया गया था कि हिंदुस्तान एयरोनोटिक्स लिमिटेड ने 2019-20 के दौरान आर एण्ड डी व्यय पर ₹ 1,232 करोड़ की उच्च राशि खर्च की थी। इसके अलावा, कम्पनी द्वारा पंजीकृत तथा वाणिज्यिकरण पेटेंट की संख्या शून्य थी। इसी तरह, भारत इलैक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड तथा ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड ने 2019-20 के दौरान आर एंड डी पर क्रमश ₹ 947 करोड़ तथा ₹ 556 करोड़ खर्च किए थे, जिसमें पेटेंट क्रमश: तीन और नौ पंजीकृत थे। इसके अलावा, उनके द्वारा वाणिज्यिकृत किए गए पेटेंटो की संख्या शून्य थी।

सार्वजनिक उद्यम विभाग ने बताया (अगस्त 2021) कि इस अध्याय पर देने के लिए उनकी कोई टिप्पणी नहीं है।